RNI No. - MPHIN/2011/39565

मासिक पत्रिका

पंचायत का सुयश

वर्ष- 10 अंक- 12 भोपाल मार्च 2021 मूल्य- 20रुपये

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भागभवेत।

मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद
का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने सांसद स्व. श्री नंदकुमार सिंह चौहान के पार्थिवशरीर को
पुष्पांजलि अर्पित की।

RNI -MPHIN/2011/39565
हिन्दी मासिक पत्रिका

पंचायत का सुयश

वर्ष– 10 अंक – 12
माह –मार्च 2021
पृष्ठ संख्या – 36 (आवरण सहित)
मूल्य – 20 रूपये

प्रधान संपादक
कैलाश अग्रवाल
संपादक
ओम प्रकाश गौड़
सहयोगी संपादक
रूपराम प्रजापति, राकेश कांडा
भोपाल संवाददाताः
राजेन्द्र अग्रवाल, राजेश कांडा,
धर्मेन्द्र प्रजापति
श्योपुर कलां संवाददाता
नितिन गौतम

प्रकाशन स्थल
जी 111/48 शिवाजी नगर, भोपाल
मप्र
मुद्रण स्थल
राजेश्वरी प्रिंटर्स प्रेस कॉम्प्लेस जोन–1
,एम.पी नगर भोपाल मप्र

पंचायत का सुयश को वेबसाइट
goodmorningmp.com
पर भी पढा जा सकता है।
ध्यान दे
प्रकाशन संबधित समस्त विवादों
का न्याय क्षेत्र भोपाल ही रहेगा।

पढियें इस अंक में.

कंमाक	विवरण	पेज नंबर
1	संपादकीय	4
2	मेरी बात	5
3	मोदीजी का ब्रम्हास्त्र आंदोलनजीवी	12
4	जिद ..जज्बे.. जुनून का ही नाम है शिवराज सिंह चौहान	15
5	शिवराज सिंह चौहान के हर कार्यकाल में मिला विकास को नया आयाम	16
6	महिला विमर्श – ऐसे न्याय को न्याय नहीं कहा जा सकता	19
7	भाजपा का आकर्षण या कांग्रेस के भविष्य की चिंता?	20
8	अब्बास से दोस्ती से जी –23 नाराज	22
9	भारत के स्पार्टाकस 'तिलका मांझी'	23
10	राष्ट्र का सांस्कृतिक एकात्म	25
11	बच्चे मन के सच्चे	29
12	गोविन्द जी ! अब नर्मदा तीरे	30
13	पंजाब के चुनाव परिणामों में दिखा किसानों के असंतोष का असर	31
15	बंगाल चुनावों में मिथुन चक्रवर्ती बनेंगे भाजपा का चेहरा?	34

संपादकीय

शिवराज सरकार के बजट की दिशा और दशा, एकदम सही और सटीक

शिवराज सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में दशा के अनुरूप दिशा पर जोर दिया हैं। इसके बाद भी यह सही है कि उससे कई बिंदु छूट भी गये हैं। प्रतीक के तौर पर ही सही उनका घ्यान रख उल्लेख किया जाना था ताकि सनद रहे कि हमारी भविष्य दृष्टि कहां टिकी हुई है। कृषि प्रधान प्रदेश में पहला बिंदु तो कृषि है उसका पूरा ख्याल रखा है लेकिन कुछ कमिया हैं। किसान आंदोलन में मध्यप्रदेश की भागीदारी ज्यादा नहीं है पर है। ऐसे में सरकार को तीनों कृषि कानूनों पर अपनी मजबूती बताने के लिये उल्लेखनीय कदम तो उठाने ही चाहिये थे उनका ऊची आवाज में उल्लेख भी होना चाहिये था. प्रदेश में फूड कारपोरेशन नगण्य सी खरीद धान और अनाज की खरीद करता है जबकि शिवराज सरकार उचित मूल्य पर खरीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसके लिये भावान्तर योजना उल्लेखनीय है जिसमें मंडी में जो भाव मिलता है उसके और मॉडल मूल्यके अंतर को सरकार किसान को देती है। इसमें अन्य फसलों के साथ अनाज और धानको भी लाने की घोषणा होनी चाहिये थी। इससे एमएसपी न सही पर उसके करीब का भाव तो सरकार देती ही है। वहीं सरकार अपनी खरीद तो खैर एमएसपी पर करती हीहै जिसके लिये पंजीयन किया जाता है। लेकिन इस बजट में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में एक भी रूपये का प्रावधान नहीं है। वैसे मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना के 2000 करोड़ से शायद इसमें कुछ रकम मिल जाए। इस बजट में एग्रो स्टार्टअप के लिये विशेष प्रावधान किया जाता तो कृषि के निजी करण पर प्रधानमंत्री जो जोर दे रहे हैं उसके दर्शन भी हो जाते. भंडारण के लिये योजना है पर इसके लिये भी अलग उल्लेख होता तोबेहतर रहता. मंडियों की संख्या बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण के प्रति भी इसी प्रकार का अपेक्षा थी। बलराम तालाब योजना के लिये एक रूपया भी नहीं जबकि प्रधानमंत्री वर्षाजल की एक एक बूंद सहेजने पर जोर दे रहे हैं. फूडप्रोसेसिंग पर भी तो कुछ बोलना चाहिये था। मुख्यमंत्री की कृषि कल्याणयोजन अन्य राज्यों के लिये प्रेरणा का कारण बन सकती है जिसमें वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में साल के छह हजार रूपये में राज्य सरकार चार हजार रूपया सालाना का अतिरिक्त सहयोग देकर किसानों का दिल जीत रही है. उसके लिये जरूर 3200 करोड़ का प्रावधान है. कृषि के खाते में 23,000 करोड़रुपया बढ़ा कर दिया है. बैट्री रिक्शा योजना, सोलर उर्जा को बढ़ावा, कांट्रेक्ट फार्मिग को बढ़ावा का मॉडल देकर भी शिवराज सरकार प्रगतिशील किसानों को रास्ता बता सकती थी. नई सीएम स्वरोजगार योजना अच्छी है लेकिन काम धंधे तो मंदे पड़े हैं इससे उम्मीद तो है पर ज्यादा नहीं इसके लिये ठोस रोडमेप अपेक्षित हैं।

बंगाल में भाजपा पूरा कर लेगी 'इंपासिबल टॉस्क'

बंगाल में मुकाबला जरा सख्त है और ममता दीदी को ष्एजष् है. कारण है उनका 43 फीसदी वोट बैंक. इसका बड़ा हिस्सा 'मुस्लिम वोट बैंक' है. ममता दीदी की 'मुस्लिम तुष्टिकरण की छबि' उनके लिए 'असेट' भी है और 'लायबिलिटी' भी. यही कारण है कि भाजपा ''51 प्रतिशत गैर मुस्लिम वोट'' पर खेल रही है. इसका बड़ा हिस्सा 'हिंदू वोट' है. ममता दीदी इसे 'ताड़' गई है इसलिए ताबड़तोड़ कई कदम उठा रही है. पर इसका हिंदू वोट पर ज्यादा सकारात्मक असर नहीं है। उससे उलट मुस्लिम वोट पर नकारात्मक प्रभाव है. भाजपा लाख कोशिश कर ले फिर भी कम ही सही हिंदू वोट में बिखराव होगा ही पर कम होगा यह तय है. ममता दीदी की सबसे बड़ी परेशानी मुस्लिम वोटों का बंटवारा है जो तय लग रहा है. भाजपा को तो न के बराबर युवा, महिलाओं और महत्वाकांक्षी लोगों का चुप्पा वोट' मिलेगा. पर पर फुरफुरा शरीफ के सिद्दीकी के कारण उनकी खुद की पार्टी के साथ कांग्रेस और वामपंथियों को भी अतिरिक्त वोट मिलेगा. वैसे भी इन दोनों का भी अच्छा खासा 'लायल' मुस्लिम वोट पहले से ही है. इसके अलावा ओबेसी की पार्टी भी जहां 40 फीसदी मुस्लिम वोट हैं वहां हैदराबाद और बिहार की तरह शानदार स्ट्राइक रेट से सफलता दर्ज कराएंगे. इस परिद्रश्य में मेरा अनुमान तो यही है कि तृणमूल और भाजपा दोनों 125–125 सीटें कम से कम निकाल लेंगे. इनमें 5–10 की उलटफेर हो सकती है पर दोनों का कुल टोटल 250 ही रहने वाला है. बची 44 सीटों में ये दोनों पार्टियों के साथ साथ बाकी दल और गठबंधन बंटवारा करेंगे। इन 44 में से 25 सीट का इंपासिबल टॉस्क' ही भाजपा की चुनौती है. यानि बहुमत के जादुई आंकड़े 148 पर स्पष्ट पहुंच. इसमें एक सीट भी कम रह गई तो भाजपा सत्ता के ताज से वंचित रह जाएगी ऐसा मेरा मानना है. इन सबके बीच मेरा दृढ़ विश्वास है कि भाजपा इस 'इंपासिबल टॉस्क' को पूरा कर लेगी और बंगाल की राजनीति को खूनखराबे के कलंक से मुक्त करवा कर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प को क्रियान्वित करेगी।

– ओम प्रकाश गौड

मेरी बात

– ओम प्रकाश गौड

भाजपा में अगली बार केरल रहेगा निशाने पर

भाजपा इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिये जी जान से लगी है. उसके एक सौ तीस से ज्यादा कार्यकताओं का बलिदान राजनीतिक हिंसा में हो चुका है जो बंगाल की खास पहचान बन गई है। पर इस बार बंगाल में बदलाव संभव लग रहा है और कहा जा रहा है भाजपा के सत्ता में आते ही विकास की राजनीति गति पकड़ेगी और हिंसा की राजनीति कहीं गहराई में दफना दी जाएगी। भाजपा की अगुआई वाले बंगाल का अगला चुनाव शांतिपूर्ण रहेगा फिर चाहे सरकार भापजा की वापस आऐ या नहीं. तो क्या भाजपा का ध्यान उस केरल की तरफ नहीं है जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता धार्मिक, राजनीतिक और राजनीतिक हिंसा का शिकार बन चुके हैं. केरल भाजपा के उपाध्यक्ष के. एस. राधाकृष्णन का मानना है कि भाजपा आलाकमान की नजरें केरल पर भी टिकी हैं। अभी राधाकृष्णन केरल में विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं. राज्य के अध्यक्ष के तौर पर के सुरेन्द्रन चुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं। वे युवा और डायनामिक नेता हैं। मेट्रोमेन के नाम से लोकप्रिय ई श्रीधरन ने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है. आशावारी डॉ. राधाकृष्णन कहते हैं कि अमित शाह और मोदीजी केरल पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। केरल में सत्ता की अल्टा पल्टी हर बार होती है और इस बार भी हो सकती है. पर साम्यवारी एलडीएफ हो या कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ दोनों का वोट परसेंटेज लगातार घट रहा है. केरल में 26 राजनीतिक संगठन इन दोनों समूहों के बीच बंटै हैं. जबकि भाजपा का एक–दो संगठनों के साथ ही गठबंधन है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है. दस साल में भाजपा का वोट प्रतिशत 10 तक पहुंच गया है. इस बार हमें बीस फीसदी वोटों की उम्मीद है. ऐसा हो पाया तो हम 10–20 सीटें जीत कर तीसरा मोर्चा बन विकल्प बनने की स्थिति में होंगे. यूडीएफ का वोट प्रतिशत 7 से 10 प्रतिशत घटा है और एलडीएफ का वोट प्रतिशत भी 4 से 7प्रतिशत तक कम हुआ है. अकेली भाजपा का ही वोट प्रतिशत बढ़ रहा है. अगर हमें अपेक्षित सीटें मिली तो हम राज्य में मध्यावधि चुनाव करवा सकते हैं फिर पूरी ताकत लगा कर सत्ता में भी पहुंच सकेंगे. राधाकृष्णन कहते हैं कि राज्य के युवाओं और महिलाओं में मोदीजी का क्रेज है. दोनों गठबंधन घोटालों में डूबे हैं. उनके हाथ से सत्ता फिसलना संभव है। हत्याओं पर डॉ. राधाकृष्णन का मानना है कि यहां धर्म आधारित जिहादी हत्याएं होती हैं और विचारधारा आधारित राजनीतिक हत्याएं भी साम्यवादियों का यकीन तो हिंसा में होता ही है. वे राजनीतिक विरोधियों की हत्याओं को जायज मानते हैं। बदले में साम्यवादियों और जिहाद समर्थक तबकों को भी हिंसा और हत्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन अपेक्षाकृत कम. मेट्रो मेन कहे जाने वाले ई श्रीधरन भी कहते हैं कि उनका झुकाव हमेशा भाजपा के प्रति रहा है और उन्हें लगता है कि भाजपा ही उनके सपनों को पूरा कर सकती है. इसलिये उन्होंने भाजपा ज्वाइन की. वे कहते हैं कि उन्होंने हर प्रकार की राजनीतिक विचारधारा के नेताओं और मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। सबने सहयोग दिया और मैंने भी पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया इसलिये मेरे चाहने वाले सभी उम्र वालें

में, सभी धर्म वालों और राजनीतिक विचारधारा वालों में हैं. मैं सबको स्वीकार करता हूं, पर मुझे लगता है कि आज की अवधि में उनके सपने भाजपा ही पूरे कर सकती है। एक जानीमानी महिला पत्रकार को दिये गये साक्षात्कार में महिला पत्रकार की सारी चतुराई के बाद भी श्रीधरन उनके सवालों के जाल में नहीं फंसे. न वे लव जिहाद पर बोले न धर्म की राजनीकि पर. वे कहते रहे कि वे विकास चाहते हैं और विवादास्पद मुद्दों पर दूरी बनाए रखते हैं।

बताया जाता है कि एक जगह पर तो यहां तक कहा जा चुका हैं कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना कर चुनावी मैदान में उतरेगी। यह बात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेन्द्रन ने कही थी। जानकार कहते है कि ऐसा हुआ तो सत्ता भाजपा के हाथ में आ सकती है. वैसे यह बात श्रीधरन ने कभी नहीं कही। और यह मामला ज्यादा तूल नहीं पकड़ सका. पर यह तय है कि श्रीधरन केरल में भाजपा को वोट दिलाने में भारी असेट साबित होंगे।

तमिलनाडु में शशिकला ने चली ढ़ाई घर की चाल

तमिलनाडु की हवा बता रही है कि इस बार डीएमके का पलड़ा भारी है और स्टालिन की अगुआई में सरकार बन सकती है। इसमें कांग्रेस की भी हिस्सेदारी होगी क्योंकि दोनों के बीच गठबंधन हो चुका है. इस हवा का बदलने के लिये शशिकला ने राजनीति से सन्यास का पांसा फैंका है और अन्ना डीएमके की सरकार बना कर जयललिता के सपने पूरे करने का आग्रह किया है। हालांकि उनके भतीजे करूणाकरण ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं न अपनी पार्टी को लेकर कोई संकेत दिया है। जयललिता की सहेली रही शशिकला ने अम्मा से ही राजनीति सीखी. जानकार कहते हैं कि जयललिता उन्ही की सलाह पर चलती थी। बीच में मतभेद रहे और शशिकला को भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल

भी जाना पड़ा. इस कारण चिन्नमा के नाम से लोकप्रिय शशिकला ने जयललिता की मौत के बाद जो राजनीति शुरू की थी उसकी अकाल मौत सी हो गई. जेल से छुटने के बाद उनका राजनीतिक आकर्षण देखा गया पर तब तक उनके विरोधी अन्ना द्रमुक पर कब्जा कर चुके थे। भाजपा उके साथ थी। भाजपा शशिकला के माध्यम से अन्ना डीएमके को बढ़ाना चाहती थी पर बात बन नहीं रही थी और अन्ना द्रमुक की उम्मीदें क्षीण हो रही थी. इसे देखते हुए शशिकला ने सन्यास का दाव चला। वो पर्दे के पीछे से अन्ना द्रमुक और भाजपा को मजबूती दे सकेंगे और द्रमुक को चोट पहुंचा सकेंगी। दक्षिण की राजनीति के जानकार जानते हैं कि यहां राजनीतिक विरोधियों को कितनी क्रूरता से निपटाया जाता है। इसी कारण शशिकला स्टालिन सरकार नहीं चाहती है। हवा भले ही स्टालिन के पक्ष में हो पर भाजपा का संगठन का ज्ञान और राजनीतिक चतुराई हो सकता है अन्ना द्रमुक की सरकार में वापसी करवा दे. इससे भाजपा की सीटें भी आने की उम्मीद की जा सकती है। दक्षिण में कमजोर भाजपा धीरे धीरे ही सही अपने पांव फैला रही है इससे शायद ही कोई इंकार कर पाएगा।

50 रूपये का प्लेटफार्म टिकट

पचास रूपये का प्लेटफार्म टिकट मोदी सरकार में ही संभव है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां तो ऐसा दुस्साहस शायद ही कर पाएं. पर यह मोदी सरकार की रेलवे को सुधारने की योजना के अनुरूप ही है। उसका कहना रहा है कि रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिये प्लेटफार्म पर बेवजह की भीड़ कम करना जरूरी है. प्लेटफार्मों के सुधार में निजी क्षेत्र को वह इसीलिये ला रही है। उच्च श्रेणी में समानांतर रेल परिचालन भी उसी का एक हिस्सा है. इससे सरकार का रेलवे में धाटा कम होगा और सामान्य लोगों यानी आम आदमी जनमें गरीब तबका ज्यादा आता है के लिये सुविधाएं जुटाई जा सकेंगी. एसी क्लास में रेलवे को घाटा नहीं है। बल्कि थोड़ा बहुत लाभ ही है। पर स्लीपर और सीटिंग रिजर्वेशन और जनरल क्लास में तो नुकसान ही नुकसान है। मोदी सरकार चाहती है कि ज्यादा लोगों को एसी की ओर आकर्षित किया जाए। एसी की सरकारी व्यवस्था के समानांतर निजी रेलों का भी संचालन हो। इस प्रकार उस पर रेल सेवायें कम करने का आरोप भी नहीं लगेगा और निजी क्षेत्र की बेहतर सेवाएं भी मिल सकेंगी. एसी की दोनों व्यवस्थाओं में किराए और सुविधाओं का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। पर एक और विकल्प तो खुलेगा जहां ज्यादा पैसा देकर बेहतर सर्विस पाई जा सकेगी। इसी कड़ी में पचास रूपये का प्लेटफार्म रेल टिकट है। वाहन पार्किंग की दरें पहले से ही बढ़ाई जा चुकी है। निजी क्षेत्र जिन रेलवे स्टेशनों का संचालन करेगा उन पर हवाई अड्डों से भी ज्यादा बेहतर और व्यापक सुविधाएं मिलने लगेगी यह तय है। बस देखना यही पड़ेगा कि कम खर्च वाले को क्या मिलता है और भरी जेब वाले क्या हासिल कर लेते हैं।

निजीकरण और सरकारीकरण के बीच संतुलन बेहद जरूरी

देश में तेज बहस चल रही है निजीकरण पर. मोदी सरकार ने सरकारीकरण का विरोध पहली बार खुलकर किया है। उन्होंने साफ कहा है कि गर्वमेंट हेव नो बिजनेस इन बिजनेस. यानि व्यापार और व्यवसाय में सरकार का कोई काम नहीं है. सरकार का काम शिक्षा स्ववास्थ्य और अन्य समाजोपयोगी काम हैं। सरकार का काम है बिजनेस को सहयोग दे न कि स्वयं बिजनेस करे. पहले समाजवादीकरण और फिर राष्ट्रीयकरण के माध्यम से सरकारी करण को लाया गया था। अब निजीकरण को लाया जा रहा है। तर्क वही है जो कृषि कानूनों के लिये कहा जा रहा है. पहले जो हालात थे उनके हिसाब से पुराने कानून ठीक थे लेकिन नये माहौल में उनमें आमूलचूल बदलाव की जरूरत है. इसलिये निजीकरण को भी विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है. पर यह सब इतिहास से सबक लेते हुए अच्छी तरह से जानते हैं कि यह विकल्प नहीं है बल्कि यह तो स्वयं ही स्वतंत्र समाधान है. यह सरकारी करण को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देगा. दोनों साथ साथ नहीं चल सकते. इनमें से कोई एक ही रह सकता है. देश जब आजाद हुआ तब संसाधनों का अभाव था. तकनीकी जानकारियां भी नहीं मिल रही थी. पर्याप्त कुशल मेनपावर यानि मानव

संसाधनों की कमी थी. तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी ढ़ांचे और निजी क्षेत्र की मिलीजुली व्यवस्थास्वीकार की थी. पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कर रहे अमेरिका की शर्ते सख्त थी. वह भारत को अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहा था. आजादी के पहले से ही पंडित नेहरू का रुझान साम्यवाद की ओर ज्यादा था. दिक्कत थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा से थी जो उन्होंने ब्रिटेन में पाई थी। इसलिये वे पूंजीवाद को भी एकदम छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। फिर शीतयुद्ध का दौर था और रूस अपना खेमा बढ़ाने को बेताब था उसने नेहरूजी की शर्तों पर ही मदद देना स्वीकार कर लिया. पंडित नेहरू ने रूसी तकनीकी यानि मशीनों और पूंजी से नये तीर्थो का स्थापना की. स्टील, भारी उद्योग, बांधों पर जोर दिया। टाटा से छिनकर उनकी कंपनी को ही इंडियन एयरलाइंस का रूप दे दिया. इसी लाइन को इंदिराजी ने अपनाया और बैंक राष्ट्रीयकरण जैसा क्रांतिकारी कदम उठा लिया क्योंकि निजी बैंक देश की अर्थव्यवस्था खासकर कृषि और गरीब आदमी को मदद देने के पक्ष में नहीं थै वे जनता से पैसा लेते और जिन औद्योगिक घरानों के थे उन्हीं

को पूंजी देते थे. कई बैंक हर साल डूबते और जनता की गाढ़ी कमाई डूब जाती। पर समय के साथ ये सरकारी कंपनियां सफेद हाथी बनने लगी और निजीकरण की व्यवस्था की ओर जाना सरकार की मजबूरी बन गई. नरसिंहाराव सरकारके वित्तमंत्री डॉ. मनमोहनसिंह ने तो उदारीकरण की जो राह खोली वह आज पूरे शबाब पर नजर आ रही है तकनीकी तलाशनी पड़ रही है. अभी भी समय है कि सरकार जल्दबाजी न करे और रूक रूक कर सोच समझ कर कदम उठाये. ताकि बाद में पछताना न पड़े। सरकार के पास पैसे की कमी है. उसे सफेद हाथियों को पालना भारी पड़ रहा है इसलिये वे उन्हेंतो बेच ही रही है, कुछ बैंकों और अन्य कंपनियों को भी बेच रही है ताकि सरकारी खजाने में कुछ पैसा आए जिससे जन कल्याण की योजनाओं को चलाया जा सके।

सरकार अभी तक तो बैंको का विलय ही कर रही थी पर इस बार तो वो कुछ बैंकों का निजीकरण करने को संकल्पित दिख रही है. पहली बार जिजीकरण की बात इतनी दमदारी से खुले आम की जा रही है।सरकार अंतिरिक्ष और रक्षा सरीखे अहम क्षेत्र सहित हर क्षेत्र में निजीकरण चाह रही है क्योंकि इससे उसे न पूंजी लगानी पड़ रही है न उत्कृष्ट तकनीकी तलाशनी पड़ रही है. अभी भी समय है कि सरकार जल्दबाजी न करे और रूक रूक कर सोच समझ कर कदम उठाये. ताकि बाद में पछताना न पड़े।

गुजरात में भाजपा की जीत

गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पानी पिला दिया था। पर उसे वह संसदीय चुनाव में नहीं दोहरा पाई। उसके बाद भी उसे उम्मीद थी कि अगले चुनाव में वह ऐसा कर सकेगी। पर बीच बीच में होने वाले चुनाव हवा का रूख बताते रहते हैं कि हवा कांग्रेस के खिलाफ है खासकर राज्य सभा चुनाव में ऐसा ही दिखा. कांग्रेस को अहमद पटेल की कमी खली. स्थानीय संस्थाओं के चुनाव को कांग्रेस बड़ा पैमाना मान रही थी जिससे राजनीतिक विश्लेषक भी सहमत दिख रहे थे. पर नगर निगम चुनावों में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को मुंह की खानी पड़ी। अब नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों और पंचायतों में भी वही परिणाम रहे. नतीजन कांग्रेस को साफ दिख रहा है कि वह प्रासंगिकता खो रही है. देश ओल्ड ग्रेट पार्टी कांग्रेस वैचारिक तौर पर कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती लेकिन वर्तमान हालात तो विपरीत चित्र बता रहे हैं। इससे कांग्रेस में मंथन का दौर से आगे बढ़ कर तूफान आया हुआ है। देखना है एक परिवार तक सिमटी कांग्रेस कौन सा रूप लेती है।

हरियाणा सरकार की सराहनीय पहल

हरियाणा सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिये सराहनीय पहल की है. उसने दस साल के लिये एक कानून लागू किया है जिसके तहत कंपनियों को 75फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को देनी होगी. दिलचस्प बात यह है कि इसी प्रकार का कानून मध्यप्रदेश में भी है पर उसकी घमक कहीं सुनाई नहीं पड़ रही है. आशा की जानी चाहिये कि शिवराज सरकार समय रहते जाग जाएगी. हरियाणा सरकार ने इसे लागू करने के लिये प्रोत्साहन के तौर पर प्रति व्यक्ति 48 हजार रुपया सालाना की सरकारी मदद देने का प्रावधान किया है. यानि सरकार 4 हजार रूपया माहवार की राशि बतौर सहायता कंपनी को देनी होगी. पर जो कंपनी पालन में कोताही बरतेगी उस पर 50 हजार रूपये तक का जुर्मानाभी लगाया जा सकेगा. कानून का परिपालन कैसा हो रहा हैं।

इसके लिये कंपनी को हर तीन माह में एक रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी होगी। राज्य सरकार के अधिकारी भी समय समय पर कंपनी में जाकर जमीनी हालात परख कर अपनी रिपोर्ट देंगे जिसके आधार पर प्रोत्साहन या दंड की कार्यवाही होगी। सरकार ने यह छूट जरूर दी है कि यह कानून 50 हजार रूपया माहवार या उससे ज्यादा वेतन पाने वालों पर लागू नहीं होगा। इससे कम वेतन वाले श्रमिक, कर्मचारी और अधिकारी ही इसके दायरे में आएंगे. यह अभी साफ नहीं है कि वर्तमान में चल रही नई–पुरानी कंपनियों को लेकरसरकार का क्या रुख रहेगा क्योंकि कानून के अनुरुप स्थानीय और बाहरी का अनुपात तत्काल लाना तो असंभव सा प्रतीत होता है. वहीं यह बात भी याद रखनी होगी कि ऐसा कानून लाने वाला हरियाणा पहला राज्य नहीं है. इससे पहले कई दूसरे राज्य भी इस प्रकार का कानून लाकर लागू करवा चुके हैं। जैसे अभी हरियाणा में इसका समर्थन और विरोध चल रहा है उसी प्रकार का समर्थन और विरोध उन राज्यों में भी चला था। पर

कुछ समय तक चलने के बाद स्वंय शांत हो गया और वही पुराना ढ़र्रा चलने लगा. अब देखना है कि हरियाणा में इस कानून का क्या हश्र होता है. लेकिन इसके साथ यह सवाल भी तो उठता है कि हरियाणा और दूसरे राज्यों को इस प्रकार के कानून लाने ही क्यों पड़ते हैं? कंपनियों का कहना है कि उन्हें स्थानीय स्तर पर योग्य स्किल्ड लेबर और कर्मचारी नहीं मिलते हैं इसलिये उन्हें बाहरी लोगों को लेना पड़ता है। यह एक हद तक ही सही है। कंपनियांनहीं चाहती हैं कि बाहरी लोग खासकर राजनीतिक दलों के नेता और अधिकारी उनके काम में दखल देकर यहां काम कर रहे लोगों को लेकर दबाव बना करव्यवस्था को प्रभावित करें. बाहरी लोगों की तुलना में स्थानीय लोग इस काममें ज्यादा सफल होते हैं इसलिये कंपनियां स्थानीय की उपेक्षा कर बाहरियों को प्राथमिकता देती हैं।

जहां तक स्किल्ड लोगों की बात है राज्य और केन्द्र सरकार स्किल डेवलपमेंट के ढ़ेरों कार्यक्रम चला रही है और वर्कफोर्स भी निकल रही है. लेकिन उसके पास अनुभव की तो कमी होती ही है. इसलिये ये लोग कंपनियों के ज्यादा काम के नहीं होते हैं। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों से पहले भी प्रशिक्षु यानि इंटर्नशिप कार्यक्रम भी तो चलते थे। इन पर न कंपनियां ज्यादा ध्यान दे रही हैं न राज्य सरकारें. कंपनियां इसके तहत युवाओं को कुछ अवधि के लिये अपनी कंपनी में रखकर कार्यअनुभव देती थी। बदले में वजीफा दिया जाता था। इससे स्किल्डऔर अनुभवी युवा कंपनियों को मिल जाते थे। उम्मीद की जानी चाहिये कि कंपनियां इस कानून को ज्यादा पारदर्शी तरीके सेलागू करेंगी और अपने स्तर पर स्किल और अनुभव देने का कोई कार्यक्रम भीहाथ में लेंगी। वहीं राज्य सरकार भी इसके जुमला या झुनझुना बनने से बचाएगी और रोजगार दिलवाकर अपनी सद्इच्छा का प्रदर्शन करेंगी।

दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल?

दिशा रवि 21 साल की जोश से लबरेज पर्यावरण संरक्षण के लिये संघर्ष करने वाली कार्यकर्ता है। वे इस काम को दो गुने जोश से करें उनका स्वागत है. पर क्या वे इस काम के लिये देश को विभाजित करने वाली संस्थाओं और ताकतों से मदद ले सकती हैं? शायद नहीं। वे सामाजिक मामलों पर भी अच्छे विचार रखती हैं और किसान आंदोलन को सकी मानती हैं। वे इसे मजबूत करना चाहती हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है. खूब जोश से करें. पर वे क्या इसके लिये देश विरोधी ताकतों से सहयोग ले सकती हैं यह सही है? कदापि नहीं. दिशा रवि ने टूल किट का निर्माण किसी सही उद्देश्य के लिये किया होता, तो किसी को आपत्ति नहीं होती पर उन्होंने इसे देश में अशांति भड़काने के लिये किया. देश की छबि को खराब करने के नापाक मंसूबे रखने वालों की टूलकिट कोसंशोधित कर उसे देश विदेश में साझा किया. इस पर सारे देश को आपत्ति है और होना भी चाहिये. यह देशद्रोह है। इस पर सवाल खड़े करने वालों के लिय`अदालत के दरवाजे खुले हैं। वे उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं फिर घबराहट क्यों? जी षडयंत्र की जड़े बहुत गहरी है, ये सब जांचसे बेनकाब हो जाएंगे इसी को लेकर

घबराहट है। देशद्रोहियों को तो सजा मिलेगी ही ऐसी सजा जो सुप्रीम कोर्ट तक मेंटिकेगी. कानून में लाख कमियां हों, खामियां हो पर इंदिराजी के हत्यारों को फांसी मिली या नहीं. मुंबई के ताज होटल मामले के पाकिस्तानी अपराधी को फांसी मिली या नहीं. यही डर दिशा रवि केसमर्थकों को सता रहा है।

सबसिडाइज्ड दरों पर कम शुल्क में निजी अस्पतालों को भी दी जाए कोविड की दवा

कोविड टीके के लिये लक्षित वर्ग के लोग अपेक्षित संख्या में आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार अफरातफरी के डर से बाकी लोगों को अभी शामिल करने से डररही है। पर निजी अस्पतालों को सरकारी सहायता से सस्ती दर से कोविड की दवा मिले तो वे भी रिजनेबल रेट पर उसे लगा सकते हैं। आधार कार्ड पेश करें औरपंजीयन करवा कर कोविड

का टीका लगवा लें। इसके लिये पर्याप्त संख्या में टीके उपलब्ध हैं. चूंकि सरकारी खजाने की सहायता से इसे सस्ता किया गया है इसलिये इसमें आधार की अनिवार्यता को चुनौती देना भी शायद संभव नहीं हो पाएगा। फिर जिन्हें आधार नहीं देना न दें और टीके नहीं लगवाये यह उनकी मर्जी पर जो करना चाहते हैं उन्हें वंचित क्यों रखा जा रहा है?

किसान आंदोलन का बज चुका है बैंड

किसान आंदोलन तीन माह से ज्यादा पुराना हो चुका है। दिल्ली की सीमाओं पर करीब करीब सन्नाटा है. आंदोलन की कमान ऐसा लगता है पंजाब के किसानों के हात से निकल कर टिकैत के हाथ में आ गई है।उन्होंने भी इसे जाट आंदोलनमें बदल कर रख दिया है। जाटों की खापें फरमान दर फरमान जारी कर रही हैं. ताजा फरमान है कि किसान चुनावों में भाजपा हो वोट नहीं दें। इसे सरकार जरा सा भी महत्व नहीं दे रही है। वह पुराने बयान पर कायम है कि इन कानूनों में खामी बताओ हम दूर करने को तैयार हैं। खामी अभी नहीं मिल रहीहो तो चलो साल डेढ़ साल आंदोलन को रोक कर विचार कर लेते हैं. किसान अपनेघरों को जाए और सरकार कानूनों को स्थगित कर दे. पर यह प्रस्ताव पंजाब के किसानों को मान्य नहीं है. वे पहले तीन कानूनों की वापसी चाहते हैं औरफिर एमएसपी पर कानून. इससे कम कुछ मंजूर नहीं। आंदोलनकारी किसान नेताओं के पास अपना कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट की कमेटीक्या रपट देती है उसका इंतजार सभी को है तभी इन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट से शायद किसी को ज्यादा उम्मीद हो क्योंकि हालात बदले हुए हैं और कृषि कानून आज की जरूरत।

मोदीजी का ब्रम्हास्त्र आंदोलनजीवी

– ओमप्रकाश गौड़,
वरिष्ठ पत्रकार भोपाल

आंदोलनजीवी कह कर मोदीजी ने ऐसा ब्रम्हास्त्र जैसा तीर चलाया है जो कल्पना के परे था और सही स्थान पर लगा है. लेकिन ऐसा कहने के साथ यह भी जोड़ना होगा, शर्ते लागू. तभी बात बनेगी अन्यथा जो लोग संदर्भ काट कर इस शब्द पर घमासान कर रहे हैं उनकी नापाक मंशा पूरी हो जाएगी। शर्त यही है कि इसे कभी शाहीनबाग तो कभी किसान आंदोलन तो कभी अलग अलग तरह से विभिन्न आंदोलनों में नजर आने वाले चेहरों से जोड़ कर देखा जाए। ये चेहरे मुखौटा लगाकर हर आंदोलन में नजर आते हैं. उनका इरादा उस आंदोलन के पवित्र लक्ष्यों को पूरा करना कदापि नहीं होता बल्कि मोदी का राजनीतिक विरोध होता है. वे उस आंदोलन पर परदे के पीछे से कब्जा कर लेते हैं और उसे अनंतकाल तक खींचने की कुचेष्टा करते हैं। इससे उस आंदोलन को क्षति पहुंचती है। जब आंदोलन शाहीनबाग और किसान आंदोलन की तरह काल्पनिक नुकसानों पर टिका हो तो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ चला जाता है. किसानआंदोलन को ही लें उसमें एमएसपी और मंडियों के धीरे धीरे खत्म होने, किसानों की जमीन कारपोरेट्स द्वारा हड़पजाने की बात कह कर तीनों कानूनों को वापस लेने की जिद पर टिका दिया है. ये तो सिर्फ उदाहरण के लिये झलक दी है बाकी पक्ष विपक्ष की कहानी तो दसियों बार दोहराई जा चुकी है। आंदोलन के खत्म होने की जैसे ही उम्मीद बनती है ये आंदोलनजीवी उसमें फांस फंसाकरउसे खत्म नहीं होने देते. अब संदर्भ से काटकर देखें तो आंदोलन तो मूल अधिकार है

बशर्ते शांतिपूर्ण हो और मूल आंदोलनकारियों के हाथ में उसकी कमान रहे, परदे के पीछे से उसे संचालित नहीं यिा जा सके। मुझे एक जानेमाने कर्मचारी आंदोलन के नेता काकथन याद है वे निजी बातचीत में कहते थे आंदोलन करो, हड़ताल करो और जब कुछ मांगे मान ली जाएं तों उसे खत्म कर दो. इसी में कर्मचारियों का भला है.वे यह भी जोड़ते थे खत्म करने के साथ ही अगले आंदोलन की तैयारी शुरू कर दो. बची मांगों में दो चार नई मांगे जोड़ दो और शुरू हो जाओ। यह क्रम सतत चलाओ. इसी में कर्मचारियों का भला है. आंदोलन करते है तो कर्मचारियों के खिलाफ की गई सारी कार्यवाही तो वैसे ही खत्म हो जाती है क्योंकि यह भी तो एक प्रमुख शर्त होती है. कर्मचारियों को दोहरा फायदा होता है।

कुछ खोना भी नहीं पड़ता और कुछ हाथ भी लग जाता है इससे कर्मचारी वर्ग कर्मचारी आंदोलन के नेताओं का मुरीद भी हो जाता है। पर कम्युनिस्ट और पुराने खांटी समाजवादी ऐसा नहीं करते. उनकी दिली इच्छा रहती है कि कुछ निलंबन हों, और कुछ बर्खास्तगी. ये लोग यूनियन पर निर्भर हो जाते हैं इससे यूनियन और आंदोलन के नेतेाओं को ताकत मिलती है. अब बात फिर आंदोलनजीवी की. संदर्भ से हटकर कहें तो आंदोलन तो लोकतंत्र की जान है. उनके बगैर लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रह सकता. इसलिये आंदोलन तो जरूर होना चाहिये पर ईमानदारी के साथ. राजनीतिक दल आंदोलन करें. ये अलग बात है उसका कोई विरोध नहीं है. बाकी संगठन भी आंदोलन करें पर आंदोलनजीवियों से दूरी बनाकर रखी जाए यह भी आंदोलन की पवित्रता के लिये जरूरी है.मोदीजी के नये एफडीआई पर ज्यादा चर्चा क्यों नहीं? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसान आंदोलन पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया था और उसमें आये दो

शब्दों में से एक शब्द था आंदोलनजीवी और दूसरा था एफडीआई जिसकी नयी व्याख्या पर जितना ध्यान जाना था वह नहीं गया। ऐसा क्यों हुआ यह विचारणीय है। वित्तीय शब्दावली के शब्द एफडीआई यानि डायरेक्ट फारेन इन्वेस्टमेंट का उपयोग खूब होता है पर अपने भाषण में मोदीजी ने एफडीआई की व्याख्या की फारेन डिस्ट्रक्टिव आडियालॉजी. एफडीआई, जो सीधा विदेशी मुद्रा निवेश था और जो कंपनियों में लग रहा है। पर मोदीजी का एफडीआई का नया रूप था विदेशी विध्वंसक विचारधारा. किसान आंदोलन में विदेशी पैसा लग रहा है।

कुछ ज्ञात और ईमारदारी वाला है तो और कुछ अज्ञात और संदिग्ध माध्यमों व स्त्रोतों से आ रहा है जिसका संज्ञान लेते हुए ईडी द्वारा कई किसान नेताओं और संस्थाओं को नोटिस जारी किये जा चुके हैं. पर विदेशी विध्वंसक विचारधारा का क्या? मोदीजी का इशारा था कि विदेशों में बैठे कुछ लोग नापाक इरादों से किसान आंदोलन को वैचारिक आधार दे रहे हैं. देश विरोधी विचारधारा और लोगों को विदेशों से किसान आंदोलन को पुख्ता करने के लिये शब्द और विचार दे रहे हैं। उन शब्दों और विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से विदेशों से फैलाया जा रहा है. जो देश में बैठे विध्वसंक शब्द और विचार सृजक हैं उनकेशब्दों और विचारों को भी विदेशी सहयोग से सोशल मीडिया के माध्यम सेफैलाया जा रहा है. मोदीजी की इस बात को संबंधित हल्कों में देखा और सराहा तो गया. विरोधियों ने आलोचना भी की पर समर्थन हो या विरोधा उसके स्वर ज्यादा तेजी नहीं पकड़पाये यही विचारणीय है। इसका कारण है कि हिंदुस्तान की सनातन विचारधारा सर्वग्राही रही है और वह हजारों साल से विदेशियों से आए धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों को आत्मसातकर रहे हैं. करीब हजार साल से ही ऐसे विचार आये हैं जिन्हें प्रयासों के बाद भी आत्मसात नहीं किया जा सका क्योंकि इन्हें अलग रखने और पहचानदेने का प्रयास सत्ता संस्थान का रहा और वे सनातन विचारों के विरोध में न सिर्फ खड़े रहे बल्कि सनातन विचारों को खत्म करने के मंसूबे भी बांधो रहे और कुछ हद तक कामयाब रहे. आजादी के बाद भी यह क्रम थमा नहीं. अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजों के सांस्कृतिक मूल्य आधुनिकता का पर्याय बन समाज में फैलाव पाते गये।

अंग्रेजों के जाने के बाद मुगल शासकों के जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को विस्तार देने की नीति और परंपरा जो अंग्रेजी पराधीन शासन में मंद पड़ गई थी वह भी अपेक्षाकृत ज्यादा तेजी से बढ़ी. पंडित नेहरू के सोवियत संघ के प्रति झुकाव ने साम्यवादी मूल्यों और संस्कृति को भी जगह दिलाई। कम्युनिस्टों को चीन का भी इसी प्रकार का राजनीतिक समर्थन मिला. इन सबके आलोक में देखें तो हम विदेशी विचारों और मूल्यों के आदी से हो गये थे. यह सब एकतरह से स्वदेशज्ञी और व्यवहारिक सा हो गया था। पर किसान आंदोलन के संदर्भ में जब मोदीजी ने विदेशी विचारों और प्रचार पर हमला किया तो तिलमिलाहट तो हुई पर वैसी नहीं जैसी आंदोलनजीवी पर देखी गई। इसके बाद भी एफडीआई की नयी व्याख्या पर काम करने की जरूरत खत्म नहीं हो जाती है। समय रहते इस पर भी काम किया जाना चाहिये ऐसी अपेक्षा तो की ही जा सकती है और की जानी चाहिये।

जिद ..जज्बे.. जुनून का ही नाम है शिवराज सिंह चौहान

- डॉ. नरोत्तम मिश्रा
गृहमंत्री मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और चौथी बार इस शीर्ष पद को संभाल कर इतिहास रच चुके शिवराज सिंह चौहान का 5 मार्च को जन्म दिन है. अमूमन में इस तरह के अवसरों पर केवल शुभ कामनाएं देने तक ही सीमित रहा हूं. लेकिन इस बार मन है भावनाए व्यक्त करने का इसलिए में यह लेख एक मंत्री के नाते नहीशिवराज जी के साथ लगभग 37 साल से साथ चल रहे एक सहयोगी .. मित्र के नाते लिख रहा हूँ. एक सूत्र वाक्य है परिश्रम की पराकाष्ठा .. जो सुनने में भी कई जगह आ जाता है लेकिन सच यह है कि इस वाक्य को जीवन मे उतारना बहुत ही बिरले लोगो के ही वश में होता है. इन्ही बिरले लोगो मे शामिल है शिवराज सिंह चौहान. इसके साथ ही जब किसी मे समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर भी खुशियां लाने की जिद हो उनके लिए काम करने का.जज्बा हो तो वह उस व्यक्ति को राजनीति में उस स्थान पर खड़ा कर देता है जहाँ आज तक बहुत कम ही लोग पहुंचे है.5 मार्च, 1959 को सीहोर जिले के नर्मदा किनारे स्थित एक छोटे से गांव जैत में मध्यमवर्गीय परिवार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ. माता–पिता के संस्कारों ने उन्हें सिखाया कि अपनी जड़ों से कभी जुदा मतहोना. जीवन में कभी ऐसा कार्य नहीं करना कि लोग तुमसे घृणा करें. शायद यही सीख उन्होंने आत्मसात कर ली. यही कारण है कि समाज का कोई ऐसा वर्ग नही हो जिसकी चिंता उन्होंने नहीं की हो. किसान पुत्र होने के कारण निश्चित ही उन्होंने किसानों का जीवन संवारने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किये लेकिन ऐसा नही है कि दूसरे वर्ग को उन्होंने कम प्राथमिकता दी. महिला और बेटियो के लिए तो उन्होंने सच मे मामा बनकर ही काम किया. चाहे वह लाडली लक्ष्मी योजना हो या कन्यादान योजना या फिर बेटियो को शिक्षित करने की योजनाएं हो उन्होंने हमेशा यही चाहा की इस आधी आबादी को समान ओरसुरक्षा कैसे दी जा सके। किसानों के लिए शिवराज जी ने क्या किया यह तो किसी से छिपा नही है। आज अगर प्रदेश में किसान खुशहाल है तो उसके पीछेकारण भी शिवराज जी है. कहने का अर्थ यह है कि शिवराज जी ने सभी वर्गों कीचिंता तो की ही उनके लिए रात दिन जी जान से जुटे रहे और आज भी जुटे है। एक स्वभाव जो अमूमन सभी राजनीति करने वालो में होता है और वह है जनता से सीधा सबन्ध रखना और उनसे लगाव रखना लेकिन शिवराज जी इस मामले में केवल दिल से सोचने वाले व्यक्तित्व है.

उनके लिए प्रदेश ओर उसकी जनता मंदिर है और वह उसके पुजारी. वह यह सार्वजनिक बोलते ही नही है वह ऐसे नेता है जोउसे अपने चरित्र में भी उतार चुके है. आम सभा मे अगर इस देश ने किसी राजनेता को जनता के सामने घुटनो के बल बैठकर उनका अभिवादन करते देखा है तो वह शिवराज सिंह चौहान ही है। जनता से लगाव उन्हें जोखिम उठाने से भी पीछे नही हटने देती. पेटलावद की एक घटना याद आती है कि जब वहां विस्फोट से कई लोगो की जान चली गयी थी लोग बहुत गुस्से में थे और सड़कों पर उतर आए थे किसी की हिम्मत नही हो रही रही थी कि वहाँ जाकर मामले को संभाले. तब मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बाद भी वह उग्र भीड़ में घुस गए और बीच सड़क पर उनके साथ बैठ गए. थोड़ी देर बाद ही भीड़शांत हो गयी। बाद में जब उनसे पूछा गया कि आप को डर नही लगा तो उनका एक ही जवाब था कि मेरी जनता से मुझे क्या डर यह सब तो मेरे ही है, ऐसे है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि शिवराज जी आज की राजनीति में एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनके साथ काम करके उनके साथ चलकर अपने को गौरवान्वित महसूस किया जा सकता है।

शिवराज सिंह चौहान के हर कार्यकाल में मिला विकास को नया आयाम

श्री शिवराज सिंह चौहान मध यप्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में अलग पहचान स्थापित करने में सफल रहे हैं. उन्होंने इस पद की गरिमा को बढ़ाया है. आज अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश के अग्रणी रहने का श्रेय उन्हें दिया जा सकता है. वास्तविकता यह है कि मध्यप्रदेश और श्री शिवराज सिंह चौहान एक–दूसरे की पहचान बन गए हैं. मध्यप्रदेश के गठन के बाद जनता के कल्याण के लिए सबसे अधिक अवधि के मुख्यमंत्री ही नहीं जनता के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री चौहान की छवि बनी है. उन्होंने हर कार्यकाल में यादगार कार्य किए हैं, जिनसे विकास के नए–नए आयाम सामने आए हैं.मध यप्रदेश में पिछले डेढ़ दशक से श्री चौहान सबसे अधिक लोकप्रिय राजनेता के रूप में जाने जाते हैं. इसके पीछे उनका कठोर परिश्रम, स्व–अनुशासन, परोपकार का भाव, करूणा से ओत–प्रोत व्यक्तित्व और राग–द्वेष के बिना हर तबके की भलाई के लिए तेजी से कार्य करने की विशिष्ट शैली प्रमुख है. उनका जन्म सीहोर जिले के ग्राम जैत में 5 मार्च 1959 को हुआ. नर्मदा मैया के किनारे गाँव होने से वे अच्छे तैराक भी बन गए. स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानने के कारण खेलों में रूचि और स्वस्थ रहने के प्रति सजगता के कारणऊर्जा से भरपूर भी रहे. कुछ वर्ष ग्राम में बचपन बिताने के बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए भोपाल आ गए थे. यहाँ विद्यालय और महाविद्यालय में छात्र परिषद के पदाधिकारी भी बने. इसके पहले उनकी अपने गांव के मजदूरोंको उचित मजदूरी दिलवाने के लिए चार मित्रों के साथ नारेबाजी और रैली से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरूआत हो गई थी. साहित्य अध ययनमुख्यमंत्री श्री चौहान ने गीता, रामायण और धर्म–ग्रंथों के साथ हीराष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों की जीवनियाँ पढ़ीं.

युवावस्था में इस उत्कृष्ट साहित्य के पठन–पाठन से उनकेलेखन और भाषण शैली का विकास हुआ। उन्होंने अपनी मौलिक चिंतन और कार्य–शैली भी विकसित की. आज भी वे प्रतिदिन एक घंटा साहित्य अध्ययन को देते हैं. उन्होंने अपने निवास में एक पुस्तकालय भी बनाया है. जन–कल्याण और जनता से जुड़ावश्री शिवराज चौहान के लिए सामाजिक और राजनैतिक संगठन उपयोगी मंच बने. इन संगठनों को उनकी नेतृत्व क्षमता से बल मिला. प्रत्येक दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए वे संगठन और समाज में अलग पहचान बनाने में सफल हुए. इसके फलस्वरूप उन्हें मध्यप्रदेश विधानसभा के लिए वर्ष 1990 में निर्वाचित होने का अवसर मिला. उन्होंने इसके पश्चात वर्ष दर वर्ष निरंतर जन–कल्याण के अभियान को गति दी. विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, मुख्यमंत्रीके रूप में हर कार्यकाल में अपनी अमिट छाप छोड़ी. जब वर्ष 1991 के आखिरीमहीनों में अटल जी ने विदिशा, रायसेन संसदीय क्षेत्र से त्यागपत्र दिया तो श्री चौहान को सांसद बनने का अवसर मिला. श्री शिवराज सिंह चौहान नेप्रत्येक हैसियत से कार्य करते हुए अभावग्रस्त परिवारों की सहायता, गरीबपरिवारों की कन्याओं के विवाह, बच्चों के शिक्षा के प्रबंध, बुर्जुगों की देखभाल और समाज के प्रत्येक वर्ग से सीधा जुड़ाव रखते हुए अपनी लोकप्रियताको निरंतर बढ़ाया है. राष्ट्रीय फलक पर कार्य से मिला अनुकूल परिवेश श्री शिवराज सिंह चौहान पाँच बार सांसद निर्वाचित हुए. नई दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के सम्पर्क के साथ ही प्रमुख समाजशास्त्रियों,वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, विचारकों, चिंतकों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथउनके सम्पर्क और संबंध विकसित हुए. ऐसे सकारात्मक और उत्साही व्यक्तियों के साथ विचार–विमर्श में भी शामिल रहे हैं। इससे उनके व्यक्तित्व को नए आयाम मिले हैं. कर्मशील होने का लाभश्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं अध्ययनशील, मननशील और कर्मशील होने की वजह से अपने संकल्प आसानी से साकार कर लेते हैं. वे जो सोचते हैं, उसे पूर्णकरने के लिए उन्हें बस इतने ही प्रयत्न करने होते हैं कि कार्य की शुरूआत से कार्य के पूर्ण होने के मध्य निरंतर अनुश्रवण का कार्य करना होता है. उदाहरण के तौर पर मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए उन्होंने वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री

बनते ही प्रयत्न प्रारंभ किए. मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाओं को साकारकरने के लिए उद्योगपतियों से सतत सम्पर्क आवश्यक था. इसके लिए की गईं इन्वेस्टर्स समिटस बहुत लाभकारी सिद्ध हुईं. मध्यप्रदेश में न सिर्फ नया निवेश आया बल्कि लाखों नौजवानों को रोजगार भी मिला. प्रदेश की प्रतिभा का पलायन भी रूका. उद्योगों के विकास से सम्पूर्ण अधोसंरचना के विकास काकार्य आसान हुआ और प्रदेश की तस्वीर को बदलने में सफलता मिली. हर कार्यकाल है विशेष मुख्यमंत्री के रूप में श्री चौहान के विभिन्न कार्यकालों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि प्रथम कार्यकाल उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, विद्यार्थियों को विद्यालय जाने केघ्लिए सायकिल प्रदाय जैसे कल्याणकारी कार्य प्रारंभ किये. बुनियादी क्षेत्रों में सुविधाएँ बढ़ाने की ठोस पहल की गई. श्री चौहान का मुख्यमंत्री पद का पहला कार्यकाल तीन वर्ष का था. द्वितीय और तृतीय कार्यकाल पाँच–पाँच वर्ष के रहे. इन दस वर्षों में मध्यप्रदेश ने विकास के नये आयाम छुए. सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में कामयाबी जहाँ तक वर्ष 2020 के मार्च माह में मध्यप्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के बाद व्यतीत एक वर्ष का प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा. न सिर्फ मध्यप्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश और विश्व के लिए भी. कोरोना महामारी नेपैर फैलाए. ऐसे संकट के समयनेतृत्व की परीक्षा होती है. बहुत से राजनेताऐसी विकराल समस्या की कल्पना मात्र से घबरा जाते हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस साहस से इस महामारी के दौर में आवश्यक फैसले लिए,उसका ही प्रतिरूप श्री शिवराज सिंह चौहान भी बने. महामारी के नियंत्रण, संक्रमित लोगों के उपचार, महामारी से बचने के लिए उपयोगी उपायों पर अमल, भावी कार्ययोजना और मनोवैज्ञानिक रूप से नागरिकों को संबल प्रदान करना बहुत मायने रखता है. सूचना प्रौद्योगिकी के भरपूर इस्तेमाल से नागरिकों का हित संवर्धन सुनिश्चित किया गया. यह बहुत संतोष का विषय है कि श्री चौहान ने स्वयं न घबराते हुए कोरोना संकट को समाधान में बदलने का प्रयासकिया. आपदा को अवसर में बदला. अनेक वर्गों के लिए सरकार का खजाना खोल दिया. कई तरह की राहत दी गईं. किसानों, विद्यार्थियों और श्रमिकों कोयोजनाओं का पैसा ऑनलाइन अंतरित किया गया. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दृढ़ इरादों का परिचय दिया। उनका संकल्प एक–एक नागरिक की जीवन–रक्षा करने और लड़खड़ाई अर्थ–व्यवस्था को संभालने का था. इन कार्यों के लिए जिस मजबूत संकल्प की आवश्यता थी, उसका परिचय शिवराज जी ने दिया. जहाँ राशि की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ उपायों पर क्रियान्वयन करते हुए रास्ता निकाला. सुशासन की सोच ने इन प्रयासों को सफल बनाया. किस कार्यकाल में किन क्षेत्रों पर रहा फोकस मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हर पारी जी जान से खेली है. वे मुख्यमंत्री के पद को सेवा का माध्यम मानते हैं। यदि सिर्फ मुख्यमंत्री के कार्यकाल की चर्चा करें तो यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुनियादी क्षेत्रों के विकास को सदैव केन्द्र में रखा है. जहाँ श्री चौहान ने प्रथम कार्यकाल में सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी, वहीं द्वितीय कार्यकाल में सिंचाई बढ़ाने का कार्य प्रमुखता से किया गया. इसके पश्चात तृतीय कार्यकाल में विद्युत उत्पादन बढ़ाने और उसके सुचारु प्रदाय पर ध्यान दिया गया. मार्च 2020 सकार्यकाल में श्री चौहान ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल की सुविधाएँ तेजीसे बढ़ाने का निश्चय किया है. इसके क्रियान्वयन की शुरूआत भी कर दी गई है।

महिला विमर्श - ऐसे न्याय को न्याय नहीं कहा जा सकता

– राकेश दुबे, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल

देश में बड़े जोर– शोर से ८ मार्च को महिला दिवस मनाया गया. इससे पूर्व आया एक न्यायालयीन निर्णय एक बार सोचने पर विवश और विचलित कर रहा है. यह बात विचलित करती है कि यदि किसी नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती करने वाले व्यक्ति को पीड़िता के साथ विवाह करने का अवसर न्यायिक व्यवस्था द्वारा दिया जाये. इसे कैसे न्याय की संज्ञा दी जाये ? वास्तव में यह प्रस्ताव शीर्ष अदालत के स्तर पर लैंगिक संवेदनशीलता को नहीं दर्शाता. हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी को पीड़िता के साथ शादी के लिये मजबूर नहीं किया जा रहा है. फिर भी यह विचारफिर भी अमान्य व असंवेदनशील की कहा जा रहा है. सही मायनो में अदालत की यह टिप्पणी न केवल अपराधियों का हौसला बढ़ाती है बल्कि महिलाओं के खिलाफ

यौन हिंसा को कमतर दर्शाती है. अनेक अर्थों में इस तरह का प्रस्ताव देना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्ष 2020 में दिये गये उस आदेश से भी बदतर है कि इस शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत देना कि वह पीड़ित युवती को राखी बांधने का अनुरोध करेगा.दरअसल, यह पहला अवसर नहीं है कि महिलाओं से जुड़े किसी मामले में ऐसा सुझाव आया हो, कई अन्य सुझाव भी लैंगिक संवेदनशीलता की दृष्टि में खरेनहीं उतरे हैं. गत वर्ष जुलाई में भी उड़ीसा उच्च न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को उस समय शादी के लिये जमानत दे दी थी, जो उस समय तक वयस्क हो चुका था. दरअसल देश के कानून में जमें सख्त दंड के प्रावधान हैं. यदि पीड़िता नाबालिग है तो अपराध और गंभीर हो जाता है, क्योंकि वह कानूनन वैध सहमति नहीं. अक्सर पीड़िताओं को कथित सामाजिक कलंक के दबाव में कई तरह के अनैतिक समझौते करने के लिये बाध्य किया जाता रहा है. कई बार लोकलाज की दुहाई देकर समाज के दबाव व डर के चलते यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति से शादी करने के लिये मजबूर किया जाता रहा है. यह विडंबना है कि कथित सामाजिक दबाव के चलते ऐसे विवाह को मान्यता दे दी जाती है. विडंबना यह है कि न्यायिक व्यवस्था भी ऐसे विवाह को मंजूरी दे देती है, वह भी न्याय के नाम पर. कितना औचित्यपूर्ण यहन्याय कह जायेगा. बदलते वक्त के साथ रिश्तों में कई तरह की जटिलताएं सामने आ रही हैं. शादी करने के झूठे आश्वासन देकर जबरन रिश्ते बनाने या लिव इन पार्टनर केमामलों में इस तरह के आरोप सामने आते रहे हैं. पीड़िता लिव पार्टनर रहने पर इस तरह के आरोप लगाये तो यह रिश्तों में खटास के मामले हो सकते हैं. लेकिन एक सभ्य समाज की मान्यताओं का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता. किसी भी समाज में बलात्कार अपराध का सबसे घृणित रूप है जो किसी भी स्त्री केशरीर, मन और आत्मा को रौंदता है. ऐसे में अपराधी सख्त सजा का हकदार होता है. ऐसी स्थिति में किसी अपराधी को उसके वीभत्स कृत्य को कानूनी मंजूरीदेकर इस तरह के अपराधों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए. अपने ऐतिहासिक न्यायिक फैसलों के बावजूद भारतीय न्यायपालिका

की लैंगिक संवेदनशीलता को लेकर सवाल उठते रहे हैं. उसे पुरुषों के वर्चस्व वाली बताया जाता रहा है. शीर्ष अदालत में महिला न्यायाधीशों की संख्या बेहद कम है. शीर्ष अदालत में 34 स्वीकृत पदों के मुकाबले दो महिला न्यायाधीश हीहैं. एक सितंबर, 2020 तक 25 उच्च न्यायालयों में स्वीकृत 1079 पदों के मुकाबले केवल 78 महिला न्यायाधीश ही थीं. इस तरह के विवादित प्रकरणों को टालने के लिये जरूरी है कि देश की अदालतों में पर्याप्त संख्या में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हो. यदि महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामलों में ऐसे अंसवेदनशील सुझाव हकीकत बनें तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे. सही मायनो में इस तरह के सुझाव जब अदालत से होकर आते हैं तो समाज में इसका असर व्यापक हो जाता है. अदालत ने जिस अभियुक्त को पीड़िता से विवाह करने का विकल्प दिया, वह पहले से ही शादीशुदा है. ऐसे सुझाव न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि परेशान करने वाले भी हैं। यह न केवल पीड़िता का अपमान है, बल्कि इससे उसके साथ हुए अपराध की भी अनदेखी होती है जो मानवता की कसौटी पर अन्याय जैसा ही है।

भाजपा का आकर्षण या कांग्रेस के भविष्य की चिंता?

कृष्णमोहन झा,
वरिष्ठ पत्रकार भोपाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आईएफडब्लूजे नईदिल्ली

कांग्रेस के जिन 23 वरिष्ठ नेताओं ने गत वर्ष पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर पार्टी में पूर्ण कालिक अध्यक्ष के निर्वाचन की मांग की थी उनमें से कुछ नेता एक बार फिर मुखर हो उठे हैं. हाल में ही राज्यसभा की सदस्यता से निवृत्त हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में इन नेताओं ने एक बार फिर एकजुटता दिखाई. इस बार पत्र लिखने के बजाय उन्होंने जम्मू में आयोजित गांधी ग्लोबल सोसायटी के बैनर तले आयोजित कथित शांति सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर अपनी बात सामने रखी किंतु इस मौके पर न तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी अथवा प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थीं और न ही गांधी परिवार के प्रति वफादार माने जाने वाले पार्टी नेताओं में से कोई इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचा. कांग्रेस के 23 वरिष्ठ असंतोष नेताओं के गुट के साथ सदस्यों ने इस कार्यक्रम में खुलकर पार्टी मसलों पर अपने विचार व्यक्त किए जिसका एक ही आशय था कि पार्टी पिछले दस वर्षों में लगातार कमजोर होती चली गई है और इसे मजबूत बनाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है. इन नेताओं ने सचेत किया कि अब अगर और देरी की गई तो पार्टी को उसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी. कार्यक्रम में मौजूद पार्टी नेताओं ने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि गुलाम नबी आजाद की बहुमुखी क्षमताओं और दीर्घकालीन अनुभवों का लाभ उठाकर पार्टी वर्तमान संकट से उबर सकती है. गौरतलब है कि अभी तक पार्टी की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि गुलाम नबी आजाद को पुनः राज्य सभा में भेजने की उसकी कोई योजना है. उधर गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट कर दिया है कि वे राज्यसभा से रिटायर हुए हैं लेकिन राजनीति में बने रहेंगे. गांधी ग्लोबल सोसायटी के कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने जिस तरह आजाद को पार्टी की जरूरत बताया उससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता था कि ये नेता आजाद को पुनः राज्यसभा में भेजने के

लिए पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की मंशा से इकट्ठे हुए हैं. इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा गौर करने लायक बात यह थी कि मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में से किसी की तस्वीर नहीं लगाई गई थी. कार्यक्रम में मौजूद नेता अपने भाषणों के जरिए यह संदेश भी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी में पूर्ण कालिक अध्यक्ष के निर्वाचन की मांग पूरी होने तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे परंतु कांग्रेस छोड़ कर जाने का उनका कोई इरादा नहीं है. पार्टी को मजबूतकरने की मंशा से ही उन्होंने यह मुहिम शुरू की है. इस अवसर पर गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ जरूर की परंतु उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि निकट भविष्य में देश के जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं उनमें वे कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान में सक्रिय भागीदारी करने के लिए तैयार हैं. अब सवाल यह उठता है कि गुलाम नबी आजाद जिस तरह पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं उसे देखते हुए क्या कांग्रेस नेतृत्व उन्हें निकट भविष्य में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी के चुनाव अभियान में कोई महत्व पूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिएतैयार होगा. राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के वक्त प्रधानमंत्री मोदी के भावुक होने के बाद से नए राजनीतिक समीकरणों के जन्म लेने के जो कयास लगाए जा रहे थे उनका गुलाम नबी आजाद ने यद्यपि खंडन कर दिया है परंतु उस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस नेतृत्व के कान जरूर खड़े कर दिए हैं. यह बात भी गौर करने लायक है कि गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ का जो सिलसिला राज्य सभा में प्रारंभ किया था वह अभी भी जारी है. उधर जम्मू में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुलाम नबी आजाद के मुख से प्रधानमंत्री मोदी की यह तारीफ रास नहीं आई तो उन्होंने आजाद केविरुद्ध न केवल नारेबाजी की बल्कि उनका पुतला भी जलाया. जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने कहा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में रहकर ही अनेक बार सांसद, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री भी बने और आज वे प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं. उनका कहना था कि गुलाम नबी आजाद तो विगत दिनों राज्य में संपन्न जिला विकास परिषदके चुनावों में पार्टी का प्रचार करने भी नहीं आए. आजाद इन आरोपों को गलत बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने घ्रधानमंत्री मोदी की तारीफ नहीं की. उन्होंने तो केवल यह कहा था कि मोदी ने अपनी जमीनी असलियत को कभी नहीं छिपाया. गौरतलब है कि कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेताओं के इस गुट को प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के वक्त दिए गए अपने भावुक भाषण में ''जी –23'' नाम दिया था. ये नेता अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं. इनमें से कुछ अभी राज्य सभा के सदस्य हैं।

जिस तरह गुलाम नबी आजाद के बदले हुए रुख के कारणपार्टी द्वारा उन्हें पुनः राज्यसभा में भेजने की संभावनाएं धूमिल दिखाई दे रही हैं उसी तरह जी–23 के अन्य सदस्यों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की उनकी मांग राज्यसभा में उनके दुबारा पहुंचने की राह में बाधा पैदा कर सकती है. इसलिए वे अब कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध खुलकर सामने आ गए हैं. उनकी मुहिम अब पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग तक ही सीमित नहीं है. उन्होंने पार्टी की रीति नीति पर भी सवाल दागना शुरू कर दिया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट पार्टी से जो समझौता किया है।

अब्बास से दोस्ती से जी -23 नाराज

पुर्व केंन्दगीय मंत्री ने बताया की पार्अी के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। आनंद शर्मा का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेतृत्व ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट से चुनावी गठबंधन का जो फैसला किया है वह गांधीवादी और नेहरूवादी सिद्धांतों के विरुद्ध है. इस गठबंधन के सूत्रधार और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि शर्मा अपने 'भविष्य के बास'' को खुश करने में लगे हैं. आनंद शर्मा ने इसके जवाब में कहा है कि मैं हमेशा भाजपा के खिलाफ रहूंगा. दरअसल जिस इंडियन सेक्युलर फ्रंट पार्टी से कांग्रेस पार्टी ने विधान सभा चुनावों के लिए तालमेल किया है उसका गठन पिछले दिनों फुरफुरा दरगाह शरीफ के पीरजादा अब्बाससिद्दीकी ने किया है जो पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थक मानेजाते थे. बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में पूर्ववर्ती वाममोर्चा सरकारके शासन काल में नंदीग्राम और सिंगूर में ममता बनर्जी जो आंदोलन किया था उसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने अब ममता बनर्जी का साथ छोड़कर इंडियन सेक्युलर फ्रंट पार्टी का गठन कियाहै. उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद नई सरकार के गठन में वह किंगमेकर की भूमिका में होंगी. चूंकि कांग्रेस भी यह मानती है कि कट्टर पंथी नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की यह पार्टी लगभग पचास सीटों के मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है इसीलिए कांग्रेस ने उसके साथ चुनावी गठबंधन कर अपना हित साधने की कोशिश की है. आनंद शर्मा का कहना है कि उनके साथ चुनावी गठबंधन करने से पहले कांग्रेस हाईकमान से अनुमति नहीं ली. जवाब में अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पार्टी हाई कमान की अनुमति से इंडियन सेक्युलर फ्रंट से चुनावी गठबंधन किया गया है।कुल मिलाकर कांग्रेस में पूर्ण कालिक अध्यक्ष के निर्वाचन की मांग से शुरू हुई लड़ाई ने अब न केवल सार्वजनिक रूप ले लिया है और अब इसमें बेहद तल्खी भी आ चुकी है. अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके जल्द थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं.कांग्रेस के लिए निःसंदेह यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब पांच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी हो चुकी है तब पार्टी के नेता जी जान से चुनाव अभियान में जुटने के बजाय एक दूसरे पर निशाना साधने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. पार्टी की यह अंदरूनी लड़ाई भाजपा की चुनावी संभावनाओं को बलवती बनाने में मददगार साबित होगी. परंतु इसके स्थिति के लिए गांधी परिवार भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता. दिक्कत यह है कि पार्टी में सोनिया गांधी के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाने वाले पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी पर अपनी पकड़तो बनाए रखना चाहते हैं परंतु पूर्ण कालिक अध्यक्ष पद स्वीकार करने से पीछे हट जाते हैं. जैसा कि पिछले दिनों हुआ जब तमिलनाडु में हुआ जब उनके बयान में उत्तर और दक्षिण के बीच भेद करते दिखाई दिए. दरअसल पार्टी को न केवल पूर्णकालिक अध्यक्ष की आवश्यकता है बल्कि उसे एक करिश्माई लोकप्रियता के धनी अध्यक्ष की कमी भी खल रही है. जब तक उसकी यहकमी पूरी नहीं होती तब तक उसे वर्तमान संकट पर विजय पाने की उम्मीद भी नहीं करना चाहिए. यह भी विडंबना है कि जिन वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की वर्तमान दुर्दशा पर चिंता जताई है उनके पास भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वे आगे बढ़ कर पार्टी के कायाकल्प का बीड़ा उठा सकें।

भारत के स्पार्टाकस 'तिलका मांझी'

– प्रवीण गुगनानी,
विचारक, समाजसेवी, बैतूल

वैसे तो विधर्मी आक्रांताओं के विरुद्ध भारत भूमि ने हजारों–लाखों लाल जन्मे हैं किंतु औपनिवेशिक आक्रांताओं के विरुद्ध जो आदि विद्रोही हुये या प्रथम लड़ाके हुये उस वीर को तिलका मांझी के नाम से जाना जाता है.तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया नाम से भी जाना जाता है. ऐसा निस्संकोच कहाजा सकता है कि 1857 के हमारे प्रसिद्ध स्वतंत्रता संघर्ष के बीज 90 वर्ष पूर्व वीर तिलका ने ही बोये थे. कहना न होगा कि 1947 तक चले हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक सेनानी के मानस मे कहीं न कहीं वीर तिलका का वीरोचित भाव व उनकी वीरगति का प्रतिशोध भाव प्रेरणा बनकर धधक रहा था. वस्तुतः वे भारतभूमि के स्पार्टाकस सिद्ध हुये हैं.

अंग्रेजो से गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से उनकी धन–संपत्ति छुड़ा लेना और उसे निध न–वंचितों को बांट देना, अंग्रेजों से हथियार छुड़ा लेना और अपने साथियों को सशस्त्र बनाने के लिए वे बड़े प्रसिद्ध हो गए थे. राजमहल (झारखंड) की पहाड़ियों मे उन्होने अंग्रेजो को लोहे के चने चबवा दिये थे. स्वतंत्रता संघर्ष के प्रसिद्ध संथाल आंदोलन के प्रणेता थे तिलका मांझी.

तिलका मांझी का जन्म बिहार के तिलकपुर ग्राम मे 11 फरवरी 1750 को पिता सुंदरा मर्मु नामक एक संथाल परिवार मे हुआ था. वीर तिलका का नाम उनके व्यक्तित्व के अनूरूप ही था. पहाड़िया भाषा मे तिलका का अर्थ होता है – लाल लाल आँखों वाला गुस्सैल व तेज तर्रार व्यक्ति. पहाड़िया समुदाय मे समाज प्रमुख को मांझी कहा जाता है. वस्तुतः उनका नाम जबरा पहाड़िया ही था. वीर जबरा के जबर्दस्त व्यक्तित्व से भयभीत रहे अंग्रेजों ने उन्हे तिलका मांझी नाम से पुकारना प्रारंभ किया था.

अपनी किशोरावस्था से ही वीर तिलका अंग्रेजों की दमनकारी व अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे. वे अपने संसाधनों पर अंग्रेजों के कब्जे के घोर विरोधी थे. बचपन मे ही उनके क्रांतिकारी मानस मे जन्मभूमि को विदेशी शासकों से मुक्त कराने की कल्पना जन्म लेने लगी थीव वे इस दिशा मे छुटपुट गतिविधियां करने लगे थे. वनवासियों के संसाधनों पर अंग्रेज सतत कब्जा जमा रहे थे फलस्वरूप 1767 मे तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था. अनेकों वनवासियों के साथ वे कदम, भागलपुर, सुल्तानगंज राजमहल मे अंग्रेजों से सतत निरंतर संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेजों को परेशान करने मे सफल सिद्ध हो रहे थे. तिलका के नेतृत्व मे चल रहे इन प्रचंड विद्रोहों से घबराए अंग्रेजों ने क्लीवलैंड नामक एक तेजतर्रार अधिकारी को राजमहल मे वनवासियों के दमन हेतु भेजा. झारखंड के जंगल, तराई, गंगातटों, ब्राम्ही नदी घाटी आदि क्षेत्रों मे

तिलका माँझी अपनी छोटी सी स्वदेशी हथियारों वाली सेना लेकर अंग्रेजों के विरूद्ध लगातार संघर्ष करते हुए मुंगेर, भागलपुर, संथाल व परगना केपर्वतीय इलाकों में छिप–छिपकर सतत निरंतर लड़ाई करते रहे. वीर तिलका कहतेथे – यह भूमि धरती माता है, यह हमारी माता है, इस पर हम किसी को लगाननहीं देंगे. इस बात से अंग्रेज प्रशासन बड़ा नाराज था और वीर तिलका को सबकसिखाना चाहता था. राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड व आयरकूट की सेना को वीर तिलका मांझी की सेना ने गोरिल्ला के माध्यम से कई कई बार छकाया व बड़ी हानि

पहुंचाई. पच्चीसों संघर्षों की इस श्रंखला मे वीर तिलका भागलपुर तक पहुँच गए. भागलपुर मे ही वीर तिलका ने 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज सेनाप्रमुख क्लीवलैंड को अपने धनुष बाण से मार गिराया. क्लीवलैंड की हत्या से अंग्रेज भयभीत तो हो गए किंतु अब दोगुनी शक्ति व वीर तिलका को खोजकर प्रतिशोध लेने व फांसी देने के लक्ष्य से उन्हे खोजने लगे।हमारे भारत मे विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध यदि हमारे वीर तिलका जैसे हजारों यौद्धाओं की गाथाएँ भरी पड़ी है तो जयचंदों की भी कमी नहीं रही. तिलका मांझी की वीर गाथा मे भी एक जयचंद आता है जिसका नाम थासरदार जाऊदाह. एक रात तिलका माँझी और उनके क्रांतिकारी साथी जब एक पारंपरिक उत्सव में नृत्य–गान कर रहे थे, तभी अचानक इस गद्दार सरदार जाउदाह ने अंग्रेजों के साथ आक्रमण कर दिया. इस अचानक हुए आक्रमण सेतिलका माँझी तो बच गये, किन्तु उनके अनेक देशभक्त साथी वीरगति को प्राप्तहुए व कई क्रांतिकारियों को बन्दी बना लिया गया. वीर तिलका माँझी वहां से वीरतापूर्वक संघर्ष करके बच निकले व भागकर सुल्तानगंज के पर्वतीय अंचल में शरण ली. भागलपुर से लेकर सुल्तानगंज व उसके आसपास के पर्वतीय इलाकोंमें अंग्रेजी सेना ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया. मैदानीक्षेत्रों मे संघर्ष की अभ्यस्त रही वीर तिलका की सेना को पर्वतीय क्षेत्र मे संघर्ष का अभ्यास ही नहीं था. फलस्वरूप उसे अपार कष्ट व अनेकों प्रकार की हानि होने लगी. पर्वतीय क्षेत्र मे अन्न व अन्य संसाधनों का भी अभाव होने लगा. इस परिस्थिति मे वीर तिलका छापामार पद्धति से अंग्रेजों को छकाते परेशान करते रहे थे. अत्यंत कष्टपूर्ण परिस्थितियों मे व अत्यल्प संसाधनों से इस प्रकार दीर्घ समय तक संघर्ष संभव ही नहीं था. इसी प्रकार के एक संघर्ष मे जब उन्होने वारेनहेस्टिंग्ज की सेना पर अपनी संथाल जाति के बंधुओं के साथ प्रत्यक्ष हमलाकिया. इस संघर्ष मे वारेन हेस्टिंग्ज की विशाल व साधन सम्पन्न सेना केसामने वीर तिलका के मुट्ठी भर साधनहीन संथाल बंधु टिक नहीं पाये व पकड़ लिए गए. इस विषमता भरे युद्ध मे भी अंग्रेज वीर तिलका को धोखे व छल से ही पकड़ पाये थे. वीर तिलका को पकड़कर उन्हे अमानवीय यातनाएं देना प्रारंभ की गई. उन्हें 4घोड़ों के पीछे मोटी रस्सियों से बाँधकर मीलों घसीटा गया. अंततः 13 जनवरी 1785 मे एक वटवृक्ष से लटकाकर वीर तिलका माँझी को अंग्रेजों ने फाँसी दे दी थी. वीर तिलका तो वीरगति को प्राप्त हुये किंतु अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे जनजातीय समाज का संघर्ष उनकी प्रेरणा से सतत चलता रहा।

वीर तिलका स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों मे व हमारे आरण्यक समाज के गीतों मे जीवित रहकर समूचे समाज को अंग्रेजों के विरुद्ध जागृत करते रहे. वीर तिलका के स्मरण का एक ऐसा ही जनजातीय गीत है जिसका अनुवाद प्रस्तुत है – तुम पर कोड़ो की बरसात हुई तुम घोड़ों से बांधकर घसीटे गए फिर भी तुम्हें मारा न जा सका तुम भागलपुर मे सरे आम फांसी पर लटका दिये तुमसे फिर भी डरते रहे जमींदार अंग्रेज तुम्हारी तिलका (तेज तर्रार) आंखों से प्रसिद्ध उपन्यासकर महाश्वेता देवी जी ने वीर तिलका की गाथा पर एक बांग्ला भाषा मे उपन्यास लिखा है – 'शालगिरर डाके'. हिन्दी के कथाकार, उपन्यासकार राकेश कुमार जी ने भी अपने उपन्यास 'हुल पहाड़िया' मे तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से बड़ा ही सुंदर चित्रित किया है. हमारे देश ने इस वीर शिरोमणि क्रांतिकारी की स्मृति मे उनके नाम से भागलपुर मे 'तिलका मांझी विश्वविद्यालय' की स्थापना की है. भागलपुर मे उनकी शहादत के स्थान पर एक प्रतिमा भी स्थापित है।

राष्ट्र का सांस्कृतिक एकात्म

– जयराम शुक्ल
वरिष्ठ पत्रकार भोपाल

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय स्वतंत्र भारत के तेजस्वी, तपस्वी व यशस्वी चिन्तकों में से एक हैं. उनके चिन्तन के मूल में लोकमंगल और राष्ट्र का कल्याण सन्निहित है. उन्होंने राष्ट्र को ध र्म, अध्यात्म और संस्कृति का सनातन पुंज बताते हुए राजनीति की नयी व्याख्या की. वे गांधी, तिलक और सुभाष की परम्परा के वाहक थे. दलगत व सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर वे वास्तव में एक ऐसे राजनीतिक दर्शन को विकसित करना चाहते थे जो भारत की प्रकृति व परम्परा के अनुकूल हो और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने में समर्थ हो. अपनी व्याख्या को उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का नाम दिया. यही दर्शन 1964 में जनसंघ के ग्वालियर अधिवेशन में अंगीकार किया गया. पण्डितजी की व्याख्याएं मौलिक और यथार्थ के धरातल पर साकार होने वाली थी. उनका दृढ़मत था कि बहुलतावादी देश में मत व मन भिन्नता हो सकती है पर इन सबके बीच राष्ट्र की एक सामान्य इच्छा नाम की कोई चीज होती है उसको आधार बनाकर काम किया जाए तो सर्वसामान्य व्यक्ति को लगता है कि मेरे मन के मुताबिक कार्य हो रहा है. 'थिंक लोकली, एक्ट ग्लोबली' यह पण्डित जी की ही अवधारणा थी जो वैश्वीकरण के दौर में बार–बार दोहराई जाती रही. पण्डित जी कहते हैं– जहाँ तक शाश्वत सिद्धान्तों तथा स्थायी सत्यों का सम्बन्ध है हम सम्पूर्ण मानव के ज्ञानऔर उपलब्धियों का संकलित विचार करें. इन तत्वों में जो हमारा है उसे युगानुकूल और जो बाहर का है उसे देशानुकूल ढालकर हम आगे चलने का विचार करें. संस्कृति ही स्वराज का प्राणतत्व है. संस्कृ ति विहीन, समाज और राष्ट्र पतनशीलता के मार्ग को उन्मुख होता है. पण्डितजी का दृढ़ मत था कि स्वराज का स्व–संस्कृति से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता हैं. संस्कृ ति का विचार न रहा तो स्वराज की लड़ाई स्वार्थी पदलोलुप लोगों की एक राजनीतिक लड़ाई मात्र रह जाएगी. स्वराज तभी साकार और सार्थक होगा जब वह अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साध न बन सकेगा.

जिस दौर में विश्व में पूंजीवाद बनाम साम्यवाद और समाजवाद का द्वंद्व चरम पर था, उसी दौर में पण्डितजी ने एकात्म मानव दर्शन को विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर, समकालीन दार्शनिकों, चिन्तकों व नीति वेत्ताओं को चमत्कृतकर दिया था. यही विचार जनसंघ का व प्रकारान्तर में भारतीय जनता पार्टी की आत्मा बना. पण्डितजी ने इस विचार को जिस सरलता से समझाया वैसी अध्यात्म दृष्टि दुर्लभ है. एकात्म दर्शन की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा – जीवन की विविधता अन्तर्मूर्त एकता का आविष्कार है और इसलिए उनमें परस्परानुकूलता तथा परस्पर पूरकता है. बीज की एकता ही पेड़ के मूल, तना, शाखाएं, पत्ते फूल और फल के विविध रूप में प्रकट होती है. इन सबके रंग, रूप तथा कुछ न कुछ मात्रा में गुण में भी अन्तर होता है. फिर भी उनके बीज के साथ केएकत्व के सम्बन्ध को हम सहज पहचान सकते है. यहां मैं पण्डितजी के दो दुर्लभ लेखों का विवेचन करेंगे, पहला लेख है– अखण्ड भारत क्यों ? इस आलेख को जनसंघ की उत्तरप्रदेश इकाई ने 1952 में एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया था. दूसरा आलेख है– 'बेकारी समस्या और उसका हल', इसे जनसंघ की दिल्ली इकाई ने 1953 में प्रकाशित किया था. ये दोनों आलेख पण्डितजी

ने तब लिखे थे जब वे महज 37 वर्ष के थे. एक युवा मन और उसका मस्तिष्क, राष्ट्र व राष्ट्रवासियों के बारे में कैसा चिन्तन करता है इन लेखों से सहज स्पष्ट है. आहत आकांक्षा के स्वर ...

अखण्ड भारत कोटि–कोटि भारतीयों की आकांक्षा है. विखण्डन की पीड़ा आज भी हृदय में टीस रही है. एकात्म मानवदर्शन के प्रणेता, चिन्तक और मनीषी पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पाँच वर्ष बाद 1952 में अखण्ड भारत क्यों ? के प्रश्न पर मार्मिक और तार्किक तरीके से इस आहतआकांक्षा को स्वर दिया. यह भारतीय जनसंघ की स्थापना का भी वर्ष था. यह वह दौर था जब खण्डित भारत के पाकिस्तान से लुट–पिट और बर्बाद होकर आने वालों की वेदना से देश क्लांत था.

जिन्होंने अंग्रेज शासकों, मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ समझौते की मेज पर देश को अंग–भंग करने के निर्णय को सहजता से स्वीकार किया उनके लिए भारत माता के रक्तरंजित होने की व्यथा सत्ता के सिंहासन की लालसा के आगे तुच्छ थी. लेकिन जिन राष्ट्रवादियों के हृदय में भारत माता की अखण्ड छविरची बसी थी उनके अन्तस में शूल चुभ रहे थे.

अखण्ड भारत क्यों? में देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एकरूपता को वैदिक काल से लेकर अब तक की स्थितियों का सहज–सरल तरीके से विवेचन किया गया है. स्वतंत्रता संग्राम के दौर में ही अंग्रेजों के संरक्षण और कांग्रेस के तत्कालीन शीर्ष नेतृत्व की सहमति से श्पाकिस्तानश् की पटकथा कैसे तैयार हुयी, ऐतिहासिक व राजनीतिक संदर्भों के साथ तथ्यों का प्रकटीकरण किया गया है.

जिस दौर में देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों पर तत्कालीन सत्ता प्रतिष्ठान का दमन चक्र चल रहा था उसी दौर में पण्डितजी ने बड़ी निर्भयता के साथ लिखा – 'भारत को खण्डित करने को लेकर 3 जून 1947 की माउन्टबेटन योजना को कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं ने स्वीकार कर लिया. रक्त बहाकर जिस देश के अखण्डता की रक्षा की गयी थी उसी देश को रक्तपात के भय सेखण्डित कर दिया।

उन्होंने आहत मन से कहा – 'रक्त की धार से लिखा हुआ इतिहास स्याही की रेखाओं से व्यक्त नहीं किया जा सकता. आलेख में तथ्यों और तर्कों के साथ पण्डितजी उद्घाटित करते है – भारत को स्वतंत्रता माउन्टबेटन योजना के कारण नहीं मिली, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, अंग्रेजों की गिरी हुयी दशा तथा भारत की राष्ट्रीय जागृति के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुयी.इसमें एक पर भी मुस्लिम मांग का प्रभाव नहीं है।

दरअसल कांग्रेस की सत्ता पिपाशा ने द्विराष्ट्र के सिद्धान्त को दूरगामी परिणाम का आंकलन किए बगैर ही स्वीकार कर लिया. कांग्रेस की भूल या सत्ताकांक्षा पर आहत पण्डितजी लिखते हैं – कांग्रेस के नेता यदि डटे रहते तथा भारत की जन जागृति की मदद करते तो अंग्रेज अखण्ड भारत छोडकर जाते औरसत्ता कांग्रेस के ही हाथ में देकर जाते.

पण्डितजी ने आज से कोई 65 वर्ष पहले ही भारत पाक के रिश्तों की भावी स्थिति का आंकलन कर लिया था. आज हम उनके आंकलन की परिणति देख रहे हैं.वर्तमान में भारत में पल रहे मुस्लिम कट्टरवाद की स्थिति व उसके परिणामका विश्लेषण भारत विभाजन के तत्काल बाद ही देश के सामने रख दिया था – कलतक जो काम लीग एक संस्था के रूप में करती थी आज वही कार्य पाकिस्तान एक राज्य के रूप में कर रहा है. निश्चित ही समस्या का परिवर्तित स्वरूप अधिकखतरनाक है।

पाकिस्तान के निर्माण में सहायक भारत के मुसलमानों की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को भी

पाकिस्तान से बराबर बल मिलता रहता है तथा भारत के राष्ट्रीय क्षेत्र में साढ़े तीन करोड़ मुसलमानों की गतिविधि किसी भी सरकार के लिए शंका का कारण बनी रहेगी।

पण्डितजी की भविष्यवाणी वर्तमान में शब्दश चरितार्थ हो रही है. पाक पोषित और प्रेरित आतंकवादियों एक बड़ी जमात आज भारत में पल रही है. ये वोलोग हैं जो स्वयं और जिनके अग्रज, पूर्वज भारत विभाजन के समय योजना यापरिस्थितिवश पाकिस्तान नहीं गए और आज भारतीय होते हुए भी पाकिस्तान की शुभेक्षा तब से ही पोषे पाले हुए हैं. पाकिस्तान व वहां तैयार हो रहे आतंकवादी गिरोहों के वे भारतीय एजेन्ट बने बैठे हैं. देश को दहलाने वाली हर आतंकी गतिविधियों में यही चेहरे उभरकर सामने आते हैं।

इन सब स्थितियों के बावजूद चिन्तक और मनीषी पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अखण्ड भारत की आकांक्षा की ज्योति को निरंतर प्रज्जवलित किए रहने की आवश्यकता बताते हैं. अखण्ड भारत को भौगोलिक सीमा से ज्यादा सांस्कृतिक सूत्र बांध सकते हैं।

देशों के नाम पर वे टुकड़े जो कभी भारत के अविभाज्य अंग थे, उन्हीं को शामिल कर अखण्ड

भारत की छवि निर्मित होती हैं. वहां हमारी सनातनी सांस्कृतिक विरासत बिखरी पड़ी है. कोई आवश्यक नहीं कि इनके एकीकरण के लिए आक्रमण या युद्ध ही हो, एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जिसकी बुनियाद में हमारी सांस्कृतिक अस्मिता रहे, जिसके आवेग से विभाजित भारत की सीमा रेखाएं मिट जाएं और अखण्ड भारत पुनरू एकाकार हो जाए. पण्डितजी लिखते है कि– अखंड भारत के आदर्श की ओर सबका रुझान होने के बाद भी अनेक लोग इसे अव्यवहारिक मानते हैं उनकी समझ में नहीं आता कि भारत अखण्ड कैसे होगा. विभाजन के पूर्व तक पाकिस्तान को भी अव्यवहारिक समझा जाता था किन्तु कुछ मुसलमानों की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास ने पाकिस्तान को सत्य–सृष्टि में परिणत कर दिया क्या भारत के 38 करोड़ लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति आज खण्डित भारत को एक करने में समर्थ नहीं होगी? कुर्वन्ने वेहि कर्माणि एकात्म मानवदर्शन के अध्येता युगपुरुष पं. दीनदयाल उपाध्याय ने अपने चिंतन के केन्द्र में 'मनुष्य' को ही रखा. कोई भी व्यवस्था 'मनुष्य' के कुशल क्षेम के बिना सफल नहीं हो सकती. पण्डितजी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के छह वर्ष बाद ही देश की अर्थनीति और उसके भविष्य का सटीक आंकलन प्रस्तुत किया था. यह आंकलन

एक विस्तारिक आलेख 'बेकारी समस्या और उसका हल' पुस्तिका के रूप में छपा था. पण्डितजी का यह विचार उस समय आया जब तत्कालीन केन्द्र सरकार पण्डितजवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नई अर्थनीति गढ़ रही थी. पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैय्यार की जा रही थी.पण्डितजी के लिये यह आहत करने का विषय था कि जिस स्वदेशी को औजार बनाकर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया उसी स्वदेशी की अवधारणा अर्थनीति के यूरोपीयकरण के पैरों तले कुचली जा रही थी. एक ओर बेकारी की समस्या बढ़ती हुयी जनसंख्या के साथ विकराल रूप लेती जारही थी वहीं दूसरी ओर ग्रामाद्योग, कुटीर धंधे दम तोडना शुरू कर चुके थे. पण्डितजी लिखते हैं– 'अर्थनीति की दृष्टि से हमारा केन्द्र होना चाहिये मनुष्य. मनुष्य को काम मिले वह सुखी रहे यही हमारा उद्देश्य होना चाहिये. मशीन मनुष्य की सुविधा के लिए है उसका स्थान लेने के लिए नहीं. मनुष्यमशीन का निर्माता है, उसका स्वामी है, उसका गुलाम नहीं. वस्तुत देश की अर्थनीति के केन्द्र में भारी उद्योगों का प्रवेश हो चुका था. स्वतंत्रता के बाद आशा यह थी कि स्वतंत्र सरकार अर्थनीति की भारतीय पारंपरिक मौलिकता को पुर्नस्थापित करेगी, संरक्षण व संवर्धन करेगी, लेकिन सब कुछ अंग्रेजों के बनाये गए ढर्रे पर ही चल निकला. सनातनी संस्कृति और पौराणिक दर्शन को आधार बनाते हुये पण्डितजी ने तब लिखा था– बेकारी की समस्या यद्यपि आज अपनी भीषणता के कारण अभिशाप बनकरहमारे सम्मुख खड़ी है किन्तु उसका मूल हमारी आज की समाज, अर्थ और नीति व्यवस्था में छिपा है. वास्तव में जो पैदा हुआ है तथा जिसे प्रकृति ने अशक्त नहीं कर दिया है काम पाने का अधिकारी है. हमारे उपनिषद्कार ने जब यह घोषणा की कि काम करते हुए हम सौ वर्ष जीवें 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिविषेच्छत्सम' तो यही धारणा लेकर चलें कि प्रत्येक को काम मिलेगा. भारत को इसीलिए कर्मभूमि कहा गया है.

पण्डितजी ने आर्थिक योजनाओं का उल्लेख करते हुये कहा – हमारी योजना का आधार होना चाहिये मनुष्य... भारत की जनसंख्या, उसके गाँव, उसका विस्तार, भारतीय जन की प्रकृति, हमारी समाज व्यवस्था, युगों से चली आयी हमारी अर्थनीति की परंपरा आदि का विचार कर आज सभी अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि भारतीय समृद्धि का आधार हमारे कुटीर व ग्रामोद्योग हो सकते हैं. पण्डितजी ने देश की भावी दशा का पूर्व से ही आंकलन कर लिया था इसलिए केन्द्र को जनसंघ की ओर से प्रस्तुत सुझावों में रोजगारपरक शिक्षा, कौशल विकास, कुटीर उद्योगों का संरक्षण व संवर्धन को वरीयता के साथ रखा गया था.

बेकारी की समस्या और उसका हल पुस्तिका में योजना आयोग के सम्मुख कांग्रेस व इंटक, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा रखेगये सुझावों का भी उल्लेख किया है. उन्होंने अर्थनीति पर अपनी ओर से गणित के छोटे से सूत्र के रूप में अर्थशास्त्र का सिद्धान्त रखते हुए विस्तार से उसकी व्यावहारिकता बताया।पण्डितजी ने तत्कालीन व्यवस्था को चेतावनी देते हुए दो टूक शब्दों में कहा – लोगों के पेट की ज्वाला न तो मीठे शब्दों से बुझती है और न शासन को गाली देने से. उसके लिये रचनात्मक प्रयत्न करने होंगे, अपनी अर्थव्यवस्था की मौलिक कमजोरियों को दूर करना होगा. पण्डितजी द्वारा लिखे एक–एक वाक्य अर्थवान हैं आज के सदंर्भ में और कल के संदर्भ के लिये भी. एक तस्वीर निश्चित ही स्पष्ट हो जायेगी कि 62 वर्ष पूर्व देश कहाँ खड़ा था, आज कहाँ पहुँचा और इस बीच क्या–क्या भूल–चूकहुयी. **(मेरा यह लेख डा.श्यामाप्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित ...युवाओं के दीनदयाल में शामिल है)** ।

बच्चे मन के सच्चे

– अंजु पांडे, समाजसेवी

कोरोना काल में जब सारे स्कूल बंद हो गए, एवं बच्चों को घर से बाहर जाकर खेलने की अनुमति भी नहीं मिली, तब मोबाइल पर बैठकर व्यर्थ समय गंवाने केबजाय दिल्ली के कुछ बच्चों ने अपने समय का सदुपयोग की जो राह निकाली, उसने उन्हें आजीवन एक अनोखे बंधन में बांध दिया. लॉकडाउन के समय शुरू हुए दिल्ली सेवा भारती के "ईच वन टीच वन?'' कार्यक्रम से जोड़कर डीपीएस, जीडी गोयंका, मॉडर्न स्कूल जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों के 12 सौ से अधिक बच्चों ने अंबेडकर बस्ती, बाल्मीकि बस्ती, रविदास कैंप, कालकाजी संजय कैंप बस्ती, के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, सुंदर–सुंदर कहानियां सुनाई, नृत्य सिखाया, आर्ट एंड क्राफ्ट में पेपर मेड गुलदस्ते, पेन स्टैंड, जैसी कई खूबसूरत चीजें बनाना भी सिखाई. यह सेवा यात्रा थी, संभ्रांत परिवारों केसर्व सुविधा संपन्न बच्चों की झोपड़ी में रहने वाले अभावग्रस्त बालकों से जोड़ने की. जिसने इनके बीच की दूरी को तय कर, दोनों ही के जीवन को अद्भुत दिशा दी. दिल्ली सेवा भारती के प्रांत प्रचार मंत्री, भूपेंद्र जी बतातेहैं कोरोना काल बीतने के बाद "ईच वन टीच वन?'' कार्यक्रम ने अब "टीन सेवा?'' का रूप धारण कर लिया है, जिसमें अब सेवा के बाद राष्ट्र भाव भीजुड़ चुका है.

यह बात है मार्च 2020 की जब कोरोना ने भारत में दस्तक दी व सारे स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए, तब दिल्ली सेवा भारती की प्रांत संपर्क प्रमुख, निधि आहूजा को उन 50 बच्चों ने फोन कर, सेवा के काम से जुडने कीइच्छा जाहिर की जो पहले से सेवा भारती द्वारा आयोजित समर एंड विंटरकैंपों में सेवा बस्तियों के बच्चों से जुड़ चुके थे. यह वह दौर था, जब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी बच्चों, बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलने का आह्वान कर रहे थे. माता–पिता डरे हुए थे व कार्यकर्ता चिंतित कैसे इन बच्चों को इस नेक काम से जोड़े. तब निधि जी ने ''ईच वन टीच वन'' कार्यक्रमके तहत गूगल फॉर्म के जरिए बच्चों से आवेदन मंगवाए, कि कौन सेवा बस्ती के बच्चों को ऑनलाइन पाढाएगा? निधिजी की खुशी का ठिकाना ना रहा, जब 1000 से अधिक बच्चे खुशी–खुशी इस कार्य के लिए राजी हो गए. अब सेवा भारती नेसंस्कार केंद्रों की निरीक्षकाओं एवं शिक्षिकाओं के सहयोग से बस्ती में रह रहे एंड्राइड फोन यूज कर बस्ती के एक बच्चे को एक संभ्रांत बच्चे से ऑनलाइन जोड़ा. सिखाने वाले को वॉलिंटियर व सीखने वाले को बडी नाम दिया गया. सप्ताह में एक बार चलने वाली इस क्लास ने ऐसे सार्थक मित्र बनाएं जिसने सारे भेद मिटा दिए. अब इस कार्यक्रम का संचालन संभाल रही दीप्ति दीदी बताती हैं कि यह सत्रचार चरणों में चला. बडी, स्टोरीटेलिंग, हॉबी एवं बुक बैंक. बडी का मतलब था आपस में मित्रता कायम करना. स्टोरी टेलिंग में वॉलिंटियर बच्चे कुछनैतिक व विज्ञान कथाएं अपने

बडी को सुनाया करते थे. हॉबी सत्र में ड्रॉइंग पेंटिंग कढ़ाई जैसी कई विधाएं ऑनलाइन सिखाई गई व बुक बैंक में बच्चों को अच्छी किताबें भेजी गई. इस अभियान में 11– 19 वर्ष के इन ढाई हजार बच्चों को प्रेरित करने व इनका मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, प्रसिद्ध बल्लेबाज शिखर ध ावन, मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा समेत कई जानी–मानी हस्तियों ने वीडियो बनाकर इन्हें शुभकामनाएं दी।कोरोना काल में शुरू हुआ दिल्ली सेवा भारती का यह शिक्षण अभियान, अब इन बच्चों के लिए जीवन भर का साथ बन चुका है. दिसंबर में जब पहली बार यह बच्चे रूबरू मिले तो यह दृश्य राम– भरत मिलाप की तरह सभी को भावविह्वल कर गया.` पुरम सेवा बस्ती के नीरज का वाक्य अभी भी सेवा भारती कार्यकर्ताओं के मनो में गूंज रहा है।जिस ने कहा अब हमारा साथ एलआईसी की तरह है, जिंदगी के साथ भी व जिंदगी के बाद भी।

गोविन्द जी ! अब नर्मदा तीरे

– राकेश दुबे,
वरिष्ठ पत्रकार भोपाल

माघ शुक्ल सप्तमी को नर्मदा जयंती है. हर साल की तरह माँ नर्मदा के घाटों पर बहुत से लोग जुटेगें. उनमें मां नर्मदा के अकिंचन भक्त, के साथ वे सफेदपोश बेटे जो एक दिन आराध ाना के बाद पोकेलेंड मशीन से माँ की कोख खोदने में मददगार बनते है, शामिल होंगे. इस बार कुछ अलग भी हो रहा है. मूलत तमिलनाडु के कौड़ीपक्कम गाँव से सम्बन्ध रखने वाले, तिरुपति में जन्मे और बनारस में पले–बढ़े अपने गोविन्दजी यानि कौड़ीपक्कम नीलमेघाचार्य गोविन्दाचार्य माँ नर्मदा के किनारे – किनारे हैं. वे गंगा भी, गोमुख से गंगा सागर तक नाप आये हैं. वैज्ञानिक, व्यवाहरिक और समग्र समाज जैसे जल जीवन जानवर और जन के लिए चिरंजीवी चिन्तन के लिए गोविन्द जी का अध्ययन अहर्निश जारी रहता है. उन्होंने राजनीति में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण इस अध्ययनवृति के कारण ही तो नहीं किया. मध्यप्रदेश की राजनीति में वैसे माँ नर्मदा का दोहन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने किया है और तो नर्मदा परिक्रमा तक राजनीतिक कारणों से हुई है. चूँकि यह अध्ययन यात्रा है, उसके लिए कुछ बिंदु – जैसे सरदार सरोवर बांध मध यप्रदेश में अपने दुष्प्रभाव दिखा रहा है. अनेक विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हुआ है. बढती–घटती ऊंचाई के खेल से दो–दो हाथ करते पीड़ित अब जान देने को उतारू हैं. किसी भी क्षण कोई अशुभ सूचना नर्मदा पर बने इसे बांध से आ सकती है. इस बांध के निर्माण, उसकी वर्तमान स्थिति और केंद्र की विभेदकारी नीति कुछ भी करा सकती है. इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा. सरकारें होंगी, राज्य और केंद्र की सरकार. वैसे हम बाढ़ प्रबंधन के हमारे नजरिये के मूल को औपनिवेशिक काल से जोड़ सकते हैं. पूर्वी भारत के डेल्टाई इलाकों में 1803 से लेकर 1956 के दौरान बाढ़ नियंत्रण को लेकर किए गए प्रयोगों का अध्ययन दर्शाता है कि यह इलाका बाढ़ पर आश्रित कृषि व्यवस्था से बाढ़–प्रभावित भूभाग में तब्दील हो गया. सबसे पहले ओडिशा डेल्टा क्षेत्र में जमीन को डूबने से बचाने के लिए नदी के तटीय इलाकों में छोटे बंधे बनाए गए थे. मशहूर इंजीनियर सर आर्थर कॉटनको 1857 में डेल्टाई इलाकों के सर्वे के लिए बुलाया गया था. उन्होंने यहक्लासिक संकल्पना पेश की थी कि 'सभी

इलाकों को बुनियादी तौर पर एक हीसमाधान की जरूरत होती है.' इस सोच का मतलब है कि नदियों में पानी की अपरिवर्तनीय एवं सतत आपूर्ति बनाए रखने के लिए उन्हें नियंत्रित एवंविनियमित किए जाने की जरूरत है. यह धारणा दोषपूर्ण होते हुए भी भारत मेंआज भी जल नीति को रास्ता दिखाती है. माधव गाडगिल और कस्तूरीरंगन समितियां पहले ही पश्चिमी घाटों की अनमोल पारिस्थितिकी को अहमियत देने और उनके संरक्षण के अनुकूल विकास प्रतिमान तैयार करने की वकालत कर चुकी हैं. लेकिन इस सलाह को लगातार नजरअंदाज किए जाने से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बदस्तूर जारी हैं. नर्मदा घाटी से भी इस तरह की खबरें रोज आती हैं. बिजली उत्पादन की मांग और बाढ़ नियंत्रण की अनिवार्यता के बीच अनवरत संघर्ष होता है. दरअसल बिजली उत्पादन के लिए बांधों के जलाशयों में भरपूर पानी की जरूरत होती है जबकि बारिश का मौसम शुरू होने के पहले इन बांधों के काफी हद तक खाली होने से बाढ़ काबू में रहेगी. किसी भी सूरत में हमारेअधिकांश बांध या तो सिंचाई या फिर बिजली उत्पादन के मकसद से बनाए गए हैंऔर बाढ़ नियंत्रण इसका दोयम लक्ष्य होता है. प्रथम लक्ष्य तो बाँध के कारणविस्थापितों का पुनर्वास होना चाहिए. विस्थापितों में वे बच्चे भी हैं जिनके सामने जिन्दगी पड़ी है. जल से मंगल की कहानी जग जाहिर है, मध्यप्रदेश में जल से दंगल नामक लिखी जा रही है।

इस कहानी को बदला जासकता है. विनोबा कहा करते थे जो कानून से हल न हो करुणा से करें, हो जायेगा. यह कहानी भी करुणा से हल होगी, कुश्ती से नहीं और नूराकुश्ती से तो बिलकुल नहीं. गोविन्द जी का अध्ययन प्रवास 23 मार्च तक चलेगा. उन्हें सब मिलेगा. क्षत–विक्षत माँ, नर्मदा के किनारे लाखों पेड़ लगाने के किस्से, रेत ढोते ट्रक, सालो से धूनी रमाये जोगी, और वे अकिंचन भी जो वन उत्पाद को माँ नर्मदा का प्रसाद मान पीढ़ियों से लगे हैं, जमे हैं।

पंजाब के चुनाव परिणामों में दिखा किसानों के असंतोष का असर

कृष्णमोहन झा.
वरिष्ठ पत्रकार भोपाल,
उपाध्यक्ष आईएफडब्लूजे नईदिल्ली

कांग्रेस शासित राज्य पंजाब की आठ नगर निगमों के चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी ने जो आश्चर्यजनक जीत हासिल की है उसने राज्य के तीन विपक्षी दलों भाजपा, अकाली दल और आम आदमी पार्टी को स्तब्ध कर दिया है. इन चुनावों में कांग्रेस अपनी शानदार सफलता पर फूली नहीं समा रही है तो वह ऐसी खुशी मनाने का पूरा अधिकार है परंतु तीन विपक्षी दलों की उम्मीदों पर मतदाताओं ने जिस तरह पानी फेर दिया है उसके कारण ये दल अपनी इस स्तब्धकारी हार काकोई बहाना खोजने की स्थिति में भी नहीं रह गए हैं. कांग्रेस पार्टी कीशानदार जीत के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह यह दावाकरने के भी अधिकारी बन गए हैं कि उनके नेतृत्व में राज्य की जनता काभरोसा पिछले तीन सालों में और मजबूत हुआ है इसीलिए नगर निगम चुनावों में अपनी पार्टी की शानदार विजय का श्रेय उन्होंने राज्य के मतदाताओं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है. पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ कहते हैं कि नगर निगम चुनावों में पार्टी की इस शानदार जीत ने साबित कर घ्दिया है कि यह जीत राज्य में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अपार लोकप्रियता की परिचायक है इसलिए कांग्रेस पार्टी दोसाल बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ेगी. गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा का पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा था और सत्तारूढ़ भाजपा–अकाली गठबंधन को हराकर दस साल बाद भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी. अकाली दल–भाजपा की गठबंधन सरकार के पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ही राज्य में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे।

नए कृषि कानूनों को लेकर अकाली दल ने गत वर्ष केंद्र में सत्तारूढ़ राजग से नाता तोड दिया था. इसलिए इस बार पंजाब के आठनगर निगमों के इन चुनावों में भी भाजपा और अकाली दल के बीच कोई गठबंधननहीं हुआ . दोनों के अलग अलग चुनाव लडने का नुकसान भी दोनों दलों को उठाना पड़ा. राज्य की आठ नगर निगमों में से सात पर कांग्रेस कब्जा करने में सफल रही जबकि गत चुनावों में राज्य की आठ नगर निगमों में से पांच पर अकाली दल–भाजपा का गठबंधन विजयी रहा था. आश्चर्य जनक बात तो घ्यह है किअकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के परिवार का गढ़ माने जाने वाले बठिंडा में भी कांग्रेस सेंध लगाने में सफल हो गई. गौरतलब है कि कांग्रेस ने 53 सालों के बाद यहां जीत दर्ज की है. सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और सांसद सनी देओल के क्षेत्र गुरुदासपुर में भाजपा को सबसे अपमान जनक हार का सामना करना पड़ा जहां नगर परिषद की सभी29 सीटों पर

उसके उम्मीदवार हार गए।

नए कृषि कानूनों के विरोध में राजग छोड़कर अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगाने वाली क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल को नगरीय निकाय चुनाव परिणामों में मिली हार ने यह संदेश दिया है कि किसानों के बीच अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए राजग छोड़ने का उसका फैसला उसे राज्य में किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित नहीं कर सका. इन चुनावों मेंआम आदमी पार्टी भी यही उम्मीद लगाए बैठी थी कि नए कृषि कानूनों के विरोध में लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसानों के असंतोष का चुनावी लाभ उसेअवश्य मिलेगा परंतु किसानों का असंतोष चुनावों में उनकी जीत सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध नहीं हो सका. अकाली दल को भी अब इस हकीकत का अहसास हो चुका है कि अगर उसने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लडा होता तो दोनों दलों को निराशा जनक हार का सामना नहीं करना पड़ता. नगरीय निकायों के चुनाव परिणामों घ्पर भारतीय जनता पार्टी की यह प्रतिक्रिया निःसंदेह आश्चर्यजनक है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का उसकी निराशा जनक हार से कोई संबंध नहीं है. असम के दौरे पर गए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है किइन चुनाव परिणामों को केंद्र सरकार के प्रति असंतोष का परिचायक नहीं माना जा सकता. केंद्रीय कृषि मंत्री का मानना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ निरंतर बातचीत का सिलसिला कभी नहीं टूटने दिया है ऐसे में पंजाब के ताजा चुनाव परिणामों को कृषि कानूनों के विरोध के रूप में देखना उचित नहीं होगा।

सवाल यह उठता है कि क्या यह मान लिया जाए कि किसान आंदोलन के दौरान हुए इन चुनावों पर वर्तमान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस तर्क की स्वीकार्यता पर भरोसा किया जाए तब तो भाजपा को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले तीन सालों में पंजाब की जनता का वर्तमान कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में भरोसा और मजबूत हुआ है. अगर ऐसा ही है तो फिर उसे अगले साल घ्होने वाले विधानसभा सभा की तैयारी में उसे अभी से जुट जाना चाहिए. उसे यह भी ध्यान होगा किअकाली दल अब उसके साथ नहीं है।

समाचार पत्रिका मासिक पंचायत का सुयश भोपाल के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से संबंधित विवरण

घोषणा फार्म 4

(नियम 8 देखिये)

1. प्रकाशन स्थान–	भोपाल
2. प्रकाशन अवधि–	मासिक
3. मुद्रक का नाम–	ओमप्रकाश गौढ
नागरिकता–	भारतीय
पता –	जी–118 / 48 शिवाजी नगर भोपाल
4. प्रकाशक का नाम–	ओमप्रकाश गौढ
नागरिकता–	भारतीय
पता –	जी–118 / 48 शिवाजी नगर भोपाल
5. सम्पादक का नाम–	ओमप्रकाश गौढ
नागरिकता–	भारतीय
पताा–	जी–118 / 48 शिवाजी नगर भोपाल

6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हो।

मै ओम प्रकाश गौढ एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकृत जानकारी एव विश्वास के अनुसार उपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

दिनांक– 10 मार्च 2021

प्रकाशक के हस्ताक्षर

ओम प्रकाश गौढ

खजुराहो नृत्य महोत्सव में शास्त्रीय नृत्यों की प्रस्तुति ।

राज्यपाल श्रीमती आंनदी बेन पटेल ने खजुराहो विश्व धरोहर श्रृंखला पर साडी ब्राण्ड की लोचिंग की।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वी.डी.शर्मा के साथ वृक्षारोपण किया।

राज्यपाल श्रीमती आंनदीबेन पटेल ने देवी अहिल्या विश्वविधालय के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित किया।